SHRI D. RAJA : Sir, I am not moving this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. Raja is not moving. Now, Shri M.P. Achuthan, are you moving?

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): No, Sir. As explained by Mr. Raja, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not moving. Okay. Now, Shri Derek O'Brien; not here. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving?

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; he is not moving. Now, Shri Sitaram Yechury; not present. So, Statutory Resolution is not moved at all. Now, Shri Narendra Singh Tomar to move the motion for consideration of the Bill.

GOVERNMENT BILL

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015

खान मंत्री; तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय **..(व्यवधान)..**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, it is the right of the Minister to explain about his Bill. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen. When the Minister moves the Motion for the Bill, he can speak also. That is the rule.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपसभापति महोदय, आज जो विषय चर्चा में है, उसमें मुख्य रूप से ऑर्डिनेंस की बात पर सब लोग आपत्ति कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह ऑर्डिनेंस इतिहास में कोई पहली बार नहीं आया है, इस से पूर्व भी ऑर्डिनेंसेज आए हैं। आजादी के बाद से 637 ऑर्डिनेंसेज आ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार सत्ता में 50 साल रही और सर्वाधिक 456 ऑर्डिनेंसेज कांग्रेस के राज में ही आए हैं। आजादी के बाद, हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता के कारण यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके सब के दल केन्द्र की सरकार में भी रह चुके हैं और

अधिकांश दलों की राज्यों में भी सरकारें हैं। किसी राज्य की सरकार या कोई दल यह नहीं कह सकता कि हम सरकार में आएंगे तो ऑर्डिनेंस के रूट में जाने के लिए आवश्यकता और urgency के अनुसार विवश नहीं होंगे। अगर आज सरकार ऑर्डिनेंस लाई है, तो हमारे नेता सदन ने आप सब के सामने इसकी आवश्यकता के बारे में बहुत विस्तार से बात रखी है।

महोदय, माइनिंग बिल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह आज देश की आवश्यकता है। हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में खेती के बाद अगर कोई दूसरा क्षेत्र रोजगार का हो सकता है, तो वह माइनिंग का क्षेत्र ही है और आज बढ़ती बेरोजगारी में रोजगार की आवश्यकता भी है। पिछले दिनों माइनिंग के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में लगातार उंगलियां उठाई जाती रहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आए, शाह कमीशन की रिपोर्ट भी आई, 2जी स्पैक्ट्रम के मामले में भी निर्णय आए और पूरे देश की एक तरह से बड़ी बदनामी हुई। मैं यह नहीं कहता कि यह हम ही कर रहे हैं, यूपीए की सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय था और पिछली यूपीए की सरकार के समय वर्ष 2009 में इस बिल को अमेंड करने की आवश्यकता हुई थी। यह अलग बात है कि यह उस समय नहीं हुआ और वर्ष 2011 में यह बिल लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया और स्टेंडिंग कमेटी ने मई, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लोक सभा समाप्त हो गई और इस कारण इस पर विचार नहीं हो पाया। आज हम पूरे देश की स्थिति को देखें तो पाएंगे कि माइनिंग के क्षेत्र में पूरी तरह ठहराव आ गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मई 2014 में हमने सरकार संभाली और उसके बाद जब हमने इसकी समीक्षा की तो मैंने पाया कि पूरे देश में माइनिंग के 63,000 से अधिक प्रकरण विचाराधीन हैं, कोई अफसर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं राज्यों में गया और वहां के मुख्य मंत्रियों से बात की, मैंने सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की और सचिवों को यहां बुलाकर भी बैठक की। सभी लोग कहते थे कि कानून बदलो, तभी काम आगे बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में खड़ी हो गई थी और इस परिस्थिति में यह आवश्यक था कि कानून में बदलाव किया जाए। माननीय उपसभापति महोदय, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए तैयारी प्रारंभ की। हमने सभी हितधारकों से संपर्क किया, राज्यों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की, ऑफीसर्स लेवल पर चर्चा हुई और जो भी हितधारक हो सकते हैं उनसे भी चर्चा करने का प्रयत्न किया। हमने इसे वेबसाइट पर भी डाला। हमारी इच्छा थी कि हम बिल के रूप में इसको शीतकालीन सत्र में लाते, लेकिन व्यापक विचार-विमर्श के कारण हम शीतकालीन सत्र में इसे नहीं ला पाए और इसलिए हम 12 जनवरी को इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे सदन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह बिल, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह देश में आवंटन की प्रकिया में पारदर्शिता बढ़ाने वाला है, विवेकाधिकार को शून्य करने वाला है, आदिवासियों को उनका हक दिलवाने वाला है और यह रोजगार का सृजन करने वाला है, इसलिए इस बिल पर विचार किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक सेलेक्ट कमेटी को भेजने का सवाल है या स्टैडिंग कमेटी को भेजने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सभा अपर हाउस है, माननीय सदस्य इस पर बारीकी से विचार कर लें और अगर और समय लेना चाहें, तो और समय बढ़ा लें, मगर इस बिल पर विस्तार से चर्चा कर लें। इसमें आपके जो सुझाव आएंगे, सरकार उन सुझावों पर जरूर संज्ञान लेगी, लेकिन यह बिल जितना विलंब से पास होगा,

[Mr. Deputy Chairman]

उतना देश का नुकसान होगा, लोगों के रोजगार का नुकसान होगा, गरीब मजदूरों का नुकसान होगा और आदिवासियों को जो इस बिल के माध्यम से डीएमएफ के माध्यम से हक मिलने वाला है उसका उनको भी नुकसान होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इस बिल पर विचार किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, now there is one amendment by Shri Jesudasu Seelam, Shri Shantaram Naik and Shri P. Rajeeve for reference of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. Now, it can be moved.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members:-

28. Shri Mani Shankar Aiyar

29. Shri Shantaram Naik

30. Shri Sharad Yadav

31. Shri Jesudasu Seelam

32. Shri T.K. Rangarajan

33. Shri Tiruchi Siva

34. Shri D. Raja

with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next Session."

Sir, here, I would also like to quote from page 546 of the 'Rajya Sabha at Work.' It says, "The general practice is that motions for reference of the Bills to Joint Committees are adopted without discussion." So, I request you, Mr. Deputy Chairman, to first put the Motion to vote. Then, some examples are also quoted in this page No. 546. It says, "Motions for reference to Joint Committees of Indian Veterinary Council Bill, 1981 – and several other Bills --- were adopted without discussion." So, this is the general practice of this House as per the 'Rajya Sabha at Work.' So, I request Mr. Deputy Chairman to put my motion to vote.

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; the question is, before the House there is

a motion already moved by the Minister. ...(*Interruptions*)... Let me speak. Now, the situation is that I have with me the motion moved by the Minister. This is number one. Then, the House has also the other Motion of amendment which is to send the Bill to the Select Committee. So, two Motions are before the House, and, usually, what is done is, both will be discussed and a decision will be taken. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: No, no. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, what do I do with the Motion moved by the Minister? ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: You can put ... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Show me the Rule? ...(*Interruptions*)... Listen, please. ....(*Interruptions*)... You can help me. ...(*Interruptions*)... No, please. ...(*Interruptions*).. You quote the rule and tell me. I am agreeable to what you say, but it should be on the basis of rule. I have before me, number one, the motion moved by the Minister, and, number two, the motion moved by hon. Members – Shri P. Rajeeve, Shri Jesudasu Seelam and Shri Shantaram Naik. I have before me two motions. How can I say that I will not allow discussion on one and I will put the other to vote? ... (*Interruptions*)... Show me the rule? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Hon. Deputy Chairman, Sir, let me put this to you and before this House that when the Government's motion has been moved by the Minister and the motion to refer it to the Select Committee has been moved, it would only be correct that the motion to refer it to the Select Committee is first put to vote. It cannot be discussed. That is what the practice has been. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is when that motion comes jointly. Here that is not the case. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: That motion has to come. ...(*Interruptions*)... That is not a Government's motion. That is a motion from this side....(*Interruptions*)...

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Sir, halfway through the motions... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no....(*Interruptions*)... Listen. ...(*Interruptions*)... Let me complete. That situation is when the motion comes jointly. Then it comes like that. Now, one section of the House is not agreeing. So, both motions are there. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, put it to vote.

[Shri Jesudasu Seelam]

...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You could help me in taking a decision.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I am helping you!

This very amendment is about whether to take it up or not. That is the essence of the amendment. We are saying, we will not pass that Bill, but please refer it to the Select Committee. So, you may take the sense of the House and then you may go ahead. ...(*Interruptions*)... If the motion is defeated, then you may go ahead. That is the only way. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have a point to make.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, before you speak, I want you to understand a point. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... I want you to understand a point that on many occasions, motion for a Select Committee comes with the agreement of both sides. That is point number one. On other occasions, Government itself moves a motion for a Select Committee. Now, what has happened is a different situation. Here...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, please take a vote.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... Listen to me. Now the situation is different. Government has moved a motion for the Bill and Government wants discussion on that. That is what they have said. You have moved the amendment and you also want a discussion.

SHRI JESUDASU SEELAM: No, Sir. ...(*Interruptions*)... We don't want a discussion. ...(*Interruptions*)... No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You don't want a discussion. ...(*Interruptions*)... Don't catch on that word. If there is a slip of the tongue ...(*Interruptions*)... Why do you catch on a slip of the tongue? Now, listen. ...(*Interruptions*)... Sit down. I am here. I am standing. ...(*Interruptions*)... Therefore, I cannot neglect one motion and put the other to vote. So, let us put both to vote. I have no problem. ...(*Interruptions*)... I have no problem if the House agrees. ...(*Interruptions*)... In any case, the question is very simple -- Do we need a discussion or not? That is the question to be decided. ...(*Interruptions*)... That is the question to be decided. ...(*Interruptions*)... That is to be decided. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, kindly listen to me. ...(*Interruptions*)... We moved the motion for an amendment to constitute a Select Committee. First, put it to vote. If it is defeated, there is enough time for discussion. ...(*Interruptions*)... There is a

second reading of the Bill; there is a third reading of the Bill. This is not the time for discussion. We request you to put my motion to vote.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, I agree. The simple question is...(*Interruptions*)... The simple question is: Do we need a discussion or not? ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, there is no need for a discussion on this amendment. There is time for discussion. There is the second reading and third reading of the Bill. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is an issue of propriety here too. ...(*Interruptions*)... One minute; we have heard everybody. So, you should also hear us out. The issue is this. There are two motions before you. And, as you have rightly said, if, for presumption sake, we take this motion up and put it to vote, what happens is, it would either get passed or not passed. If it gets passed, then what is the meaning of having a discussion in this House? Then there is no point in having a discussion. ...(*Interruptions*)... One minute. Now listen. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: There won't be any discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: So, the House has the right and privilege; you as well as our Members, both, are part of this House and everybody has the right to speak his mind on the subject. ...(*Interruptions*)... So, that discussion precedes. That is the propriety. Then, as you have ruled, Mr. Deputy Chairman, Sir, first, there will be a discussion on the official motion and then you will vote for both the motions. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we are very clear that if the amendment, as moved, is not disposed of, we cannot proceed because the amendment is to refer this Bill to a Select Committee. Let the Select Committee scrutinise the Bill. How can we start a discussion without disposing of the amendment to refer it to a Select Committee? This Government has dispensed with the Standing Committees. Now, they want to completely bypass parliamentary scrutiny. We are unable to accept this. Yes, I say that you have a right; all of us have a right. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: You are denying the Parliament its right to scrutiny. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Let that right be decided. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the rationale of saying that there should be no discussion? Tell me.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have one additional point. We are not against the discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Show me the rule which says that it should be taken up without discussion. Show me the rule. ...(*Interruptions*)... Yes, Mr. Ashwani Kumar.

SHRI ASHWANI KUMAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have a point of order. Sir, no law, no rule, exists in a vacuum, and the Leader of the House knows that reason is the life of law. What is our amendment? Our amendment is that this House should not discuss the matter and...(*Interruptions*)... One minute. Allow me...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: How can you take away my right? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him say...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am on a point of order. If I have a right to move my amendments, we have moved the amendments. The amendments are to the effect that the matter should be referred to the Select Committee. If that is the view of the majority of the House, there can be no discussion. That is the whole point. ...(*Interruptions*)... You cannot put the cart before the horse. That is the logic of the Amendment. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Why are you afraid of discussion? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, what you forget is that this is only an amendment. I have to go by the rules of the amendment. That is the point. ...(*Interruptions*)... Your motion is an amendment and I have the main motion with me. So, you are saying to give importance only to the amendment and not to the main motion. How can I do this? ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): The amendment should be taken up first. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How does the House know...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी **...(व्यवधान)...**

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, the nature of the amendment...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That I understand. That is the point. ...(*Interruptions*)... That I appreciate. Yes, Nareshji... (*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, नियमावली में बहुत से नियम ऐसे हैं, जो स्पष्ट नहीं हैं। इसी के कारण आज यह प्रश्न पैदा हुआ कि अमेंडमेंट वाला सेलेक्ट कमेटी का जो रिज़ॉल्यूशन है, वह पहले लिया जाए या गवर्नमेंट ने जो बिल रखा है, वह पहले लिया जाए? इसका पहले भी ... श्रीमन्, उस दिन मैंने एक प्रश्न उठाया था कि **...(व्यवधान)...**मैं जो बात **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is not the issue. The issue is that both have to be discussed and voted finally. That's all.

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं श्रीमन्, अगर नियमावली में कोई नियम स्पष्ट नहीं है, तो हाउस को हरदम सर्वोच्च माना गया है, सदन को सर्वोच्च माना गया है। अगर नियम स्पष्ट नहीं है, तो आप सदन की राय ले लीजिए। आप सदन की राय के अनुसार काम करेंगे। **...(व्यवधान)...** पीठ अपने आप कोई अधिकार नहीं ले सकता। आप सदन की राय ले लीजिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have a point of order under Rule 114. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Rajeeve...(*Interruptions*)... आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...** I will deal...(*Interruptions*)... Mr. Rajeeve, you show me a rule which says that a Select Committee amendment should be voted then and there. Where is that rule?

SHRI P. RAJEEVE: The rule is there...(*Interruptions*)...

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड)**:** गरीब जनता के हित में **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You allow him...(*Interruptions*)... I have called Mr. Rajeeve. ...(*Interruptions*)...I have called Mr. Rajeeve to speak; nobody else. ...(*Interruptions*)...

श्री तरुण विजय : आप गरीबों का विरोध कर रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है**...(व्यवधान)...** गरीबों का विरोध करते हैं**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun Vijay, please don't do that. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have two points. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule? ...(*Interruptions*)...

श्री मोहम्मद अली खान (आन्ध्र प्रदेश)**:** क्या बात कर रहे हैं आप?**...(व्यवधान)...**

†(شری محمد علی خان : کیا بات کر رہے ہیں آپ ....(مداخلت

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? Please ask him to behave. ...(*Interruptions*)... Ghulam Nabi ji, please ask him to behave. ...(*Interruptions*)... Yes, Mr. Rajeeve, tell me. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have two points. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I want Rule. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is 114.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't want 'Parliament at Work'; I am guided by the Rules. I have told you. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is 114. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is one final Rule, and, that is, the House will decide it. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it was told that this is as an amendment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve is speaking. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: The House is supreme. Let this be settled once for all. ...(*Interruptions*)... The House is supreme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I know. Let him speak. Please allow him to speak. ...(*Interruptions*)... Yes, Mr. Rajeeve.

SHRI P. RAJEEVE: First point is that you told the House that this is an amendment. Rule 114 says, "If a motion that the amendment be taken into consideration is carried, the Chairman shall put the amendment to the Council in such manner as he thinks most convenient for its consideration". ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It says, "in such a manner as he thinks..." ...(*Interruptions*)... It says, "in such a manner as he thinks..."

SHRI P. RAJEEVE: Yes. If the Chairman thinks that...(*Interruptions*)... Let me complete. The general practice is, as I quoted earlier, that the Select Committee motion is passed without a discussion. Why? It is because if it is passed....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was unanimous. It was from both the sides.

SHRI P. RAJEEVE: Not only that, Sir. If it is passed, the Select Committee will hear the stakeholders and that Committee will discuss all these things, then, there is no

need of a discussion at this time.

श्री प्रकाश जावडेकर : यह किसने कहा?...**(व्यवधान)**...

SHRI P. RAJEEVE: If it is defeated... ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Select Committee is not an alternative to the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: The House can't discuss this. ..(*Interruptions*)... The Select Committee has to...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: That is the time for discussion here. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is an advantage; I agree. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I have been trying to speak since long. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask them to sit. ...(*Interruptions*)... Mr. Rajeeve, the Rule you read is under 'Bills other than Money Bills returned by House with amendments'. That is what you said. So, what you said is not relevant here. ...(*Interruptions*)... Now, the Leader of the House.

SHRI P. RAJEEVE: The Chairman told that this is taken up as an amendment. ...(*Interruptions*).. Only because of that, I quoted it. Otherwise, I would not have quoted it.

THE MINISTER OF FINANCE; THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS; THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, we are in complete disagreement with the point of view that Mr. Ashwani Kumar, Mr. P. Rajeeve and Mr. Anand Sharma made, and, that point of view is framed in this manner that 'if a motion comes that a Bill be referred to a Select Committee because, purportedly, I believe, the numbers are on my side'. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : क्या बोल रहे हैं आप?...**(व्यवधान)**... क्या बात कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**...

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडु) : सर, थोड़ा रनिंग कमेंटरी बंद करवाइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. Let us try to understand this. So, listen. ...(*Interruptions*)... Have an open mind. ...(*Interruptions*)... Listen. Have an open mind.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not allowing. ...(*Interruptions*)... Don't do this. ...(*Interruptions*)...

3.00 P.M.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, the Finance Minister is... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed him. You sit down. ...(*Interruptions*)... He is the Leader of the House; he can speak. The Leader of the House and the Leader of the Opposition can speak. With my permission, he is standing. You sit down. ...(*Interruptions*)... Please.

SHRI ARUN JAITLEY: That my motion, therefore, should be taken up without a discussion and a voting takes place.

Sir, a discussion in Parliament is not an empty formality. A discussion is the art of persuading other Members to agree with your point of view. When you discuss a Motion that it be referred to a Select Committee, Members are entitled to make up their minds, the Parties are entitled to make up their minds, whether there is an element of urgency; whether larger public interest will be served in referring it to a Select Committee; or, whether the public interest demands that it should be passed right now.

For even that elementary exercise of making up your mind, some semblance of discussion has to take place. Now, kindly take the converse of what Mr. Anand Sharma and Mr. Ashwani Kumar says. If a particular group has a majority in a House, can he ever say that my Motion be taken up; tomorrow, it will extend, my Bill be taken up and passed without a discussion? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: That is what you are doing. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sorry, it can never happen. ...(*Interruptions*)... It can never happen. ...(*Interruptions*)... Then the logical extension of this absurdity is that whoever ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Not absurdity. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I call it an absurdity. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Absurdity is unparliamentary. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: That is unparliamentary. ...(*Interruptions*)...

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (Madhya Pradesh): Everything has happened in Lok Sabha. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, even when in the House of People, a particular party has a majority, ...(*Interruptions*)... a discussion always takes place even when it is known in advance that the majority is on one side. No Resolution, no Motion, no Bill is passed without a discussion. Now today, as per the procedure, three things were possible. One, you had a Statutory Motion disapproving the Ordinance. Two, you had the Bill itself or Motion by the Minister that my Bill be accepted. Three, a Motion that no, it need not be accepted; it should be referred to a Select Committee. Mr. Raja and others withdrew the first Motion. So, two are left. What if in relation to a subject matter there are two Motions simultaneously before the House? It is not the first time it has happened. Now, kindly see page 618 of Rajya Sabha at Work. Come to the fourth paragraph. Here, the two Motions were the Statutory Resolution as also the Bill. Now, the question was: Will both be taken up together or one be taken up after the other? Now, if the Statutory Motion is allowed, the Bill fails. This was the argument. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: It is not the Statutory Motion, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, fourth paragraph: Names of all Members from whom notices are received are included in the List of Business. The Resolution is moved first and then the Minister concerned moves for consideration of the related Bill and thereafter a combined discussion takes places on both.

SHRI P. RAJEEVE: That is always here. ...(*Interruptions*)... That is always here. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: That is not for amendment. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: That is entirely different. ...(*Interruptions*)... Sir, the Leader of the House is a very experienced Parliamentarian. ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I have one point. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. ...(*Interruptions*)... Let him complete. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, it is unheard of in Parliamentary practice that I

want to oppose the Motion for referring to a Select Committee. Can anybody say that a discussion on this Motion should not be allowed? Is discussion alien to a Parliamentary practice? In order to make up its mind, whether the matter should go to a Select Committee or not, at least, some elementary discussion has to take place. Where do we get this practice from and whatever ruling is given on this will be a ruling for all times to come that if somebody says, I by majority say, a discussion should not be held, then a discussion will not be held and it will be passed. It will be completely destructive of Parliamentary practice.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, amendment is entirely different from Statutory Motion. ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I have one point. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have to give the ruling. ...(*Interruptions*)... No more discussion. ...(*Interruptions*)... I have to decide. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, amendment is entirely different from Statutory Motion. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood. ...(*Interruptions*)... I understood. ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I have only one point. Before you give your decision, please consider the following. When two mutually-contradictory Motions are before you and you have to take a call, please do not interpret a rule in a manner that the Motion which in the scheme of things must be taken up first gets relegated to a secondary position.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; it is not like that.

SHRI ASHWANI KUMAR: Otherwise, our amendments become infructuous. Therefore, you defeat the voice of the majority. The sense of the House is reflected by the majority. And please do take this into consideration. ...(*Interruptions*)... We do not want it ..(*Interruptions*).. to be bulldozed. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. I got your point. ...(*Interruptions*)... I have to give the ruling. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, रूल 268 में Department- Related Standing Committee के बारे में लिखा हुआ है। आप इसका रूल 273 पढ़ लीजिए। इसमें बहुत क्लीयर दिया गया है, नियमावली में नियम के अंतर्गत अगर कमेटी बनाई गई, तो इसीलिए बनाई गई कि अगर कोई भी बिल या कोई भी ऑर्डिनेंस आएगा, तो वह कमेटी को जाएगा और कमेटी में डिस्कशन होने

के बाद ही वह यहां आएगा। रूल 273 में इसका प्रोसीजर बहुत क्लीयर दिया गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is Select Committee.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, सेलेक्ट कमेटी इसीलिए बनाई गई, सेलेक्ट कमेटी का प्रोविज़न इसीलिए दिया गया कि अगर एक हाउस में कोई चीज़ पास हो जाती है, तो दूसरे हाउस में सेलेक्ट कमेटी बनेगी। इसके लिए इसमें प्रोसिजर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is Standing Committee. ...(*Interruptions*)... Okay. It is over. ...(*Interruptions*)... That is the Standing Committee.

SHRI ANAND SHARMA: I am on a different point. Sir, let me read from rule 125. It says, "Any member may (if the Bill has not already been referred to a Joint Committee of the Houses, but not otherwise) move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee and, if such motion is carried, the Bill shall be referred to a Select Committee, and the rules regarding Select Committees on Bills originating in the Council shall then apply". This rule is final. It has to be disposed of. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप सेलेक्ट कमेटी का जो भी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करिए, जो मोशन दिया गया है, उस पर एक साथ बहस करिए और उसके बाद वोट करिए। इसमें किसी भी का भी विरोध कहां है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, this discussion was very lively. I too benefited from it. I am also trying to understand it. I am also one among you. ...(*Interruptions*)... No, no. Listen.

The first point is – it has been referred by Shri P. Rajeeve or some other Member – regarding Select Committee motion, immediately put it to vote without discussion. Those are, as far as I know, and I don't think there is any other precedent, resolutions with the concurrence of the House, with the sense of the House. ...(*Interruptions*)... Let me speak. They are either moved by the Government side or this side, but it is with the consent of both. ...(*Interruptions*)... Let me speak. If it is not, show me a precedent; I will come to you. Those are motions for Select Committee amendment. Now, when a Member, a Private Member — I mean to say a Member not from the Government side -- moves a resolution for amendment, to my knowledge, there is no precedent that such a motion, when objected to by the other side, is put to vote without discussion. ...(*Interruptions*)... Let me say there is a... ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: As per the rules...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, listen. I am saying 'to my knowledge'

there is no such precedent. That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... If there is a precedent, I am amenable to correction. Point it out. Can any one of you point it out? ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, as per the rule... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am going by the rule. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, if today there is no precedent, this house will make one. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete. ...(*Interruptions*)... Let me complete. I am going by the rule. It is because Shri P. Rajeeve quoted from the *Rajya Sabha at Work*, I said there is no such precedent. Now, with regard to this, what is my position? I have before me two motions. One is Government motion. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... The second one is Select Committee motion. The procedure usually adopted is that both will be discussed and, then, the Select Committee amendment will be put to vote, either to be accepted or rejected. Then, the motion will stand adopted or negatived. That is the procedure. ...(*Interruptions*)... Therefore, what you are asking is... ...(*Interruptions*)... When you ask that it should be put to vote... ...(*Interruptions*)... Listen, listen. What you are asking is that there should be no discussion. Let me ask you. Can the Chair agree to that?

SHRI P. RAJEEVE: Can you give one example or precedent from *Shakdhar and Kaul* or from *Rajya Sabha at Work* of any Select Committee motion being passed with discussion? There is no distinction between the two, with consensus or without consensus. Rules are applicable to all. It is irrelevant whether there is consensus or no consensus.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, you go through the proceedings, Selection Committee Motion will be there. It will be discussed in the House and then a decision will be taken. How can you say, 'without discussion take a decision?' ...(*Interruptions*)... These are not contradictory Motions. ...(*Interruptions*)... What is the logic behind saying 'no discussion?'

SHRI ANAND SHARMA: Sir, Rule 124 says 'discussion' and Rule 125 makes it very clear that if the Motion is carried to refer it to the Select Committee, then Rule 125 will prevail. First Rule 125, not Rule 124 for discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, what is there in Rule 125? ...(*Interruptions*)... Rule 125 does not say that there should not be a discussion. ...(*Interruptions*)... Rule

125 does not say that there should not be a discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, where does it say that the Select Committee Reference must have a discussion? Kindly show me the Rule, Sir. ...(*Interruptions*)... Which Rule says that? ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Which Rule says that? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is no Rule in the Rule Book which forces this House...(*Interruptions*)... Rule 125 has to be respected. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You see Rule 124. ...(*Interruptions*).... It says during discussion...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You see that. ...(*Interruptions*)... You have to read Rule 124 and Rule 125 together. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Without reading Rule 124 you cannot read Rule 125. ...(*Interruptions*)...

श्री बसावाराज पाटिल (कर्नाटक): उपसभापति जी, बिना चर्चा के **...(व्यवधान)...** कैसे बना सकते हैं? **...(व्यवधान)...** चर्चा अनिवार्य है। **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. It cannot be. ...(*Interruptions*)... If the House decides to refer it to a Select Committee...(*Interruptions*)... That is why Rule 125 comes. ...(*Interruptions*)... Otherwise, Rule 125 should have been Rule 124.

श्री प्रकाश जावडेकर: आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. But you want it without discussion. Why do you want it without discussion? ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? **...(व्यवधान)...** आप चर्चा से क्यों डरते हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री बसावाराज पाटिल: सर, **...(व्यवधान)...** सदन में चर्चा होने के बाद **...(व्यवधान)...**

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the issue is very simple. As the hon. Leader of the House has said, they have got the right to move an amendment to refer it to the Select Committee. There is a provision for discussion. From Rule

121 to Rule 128, the entire provision is there as to when a Bill passed by the other hon. House comes here; Rule 124 precedes Rule 125. ...(*Interruptions*)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): No. ...(*Interruptions*)... Rule 125 is a separate Rule. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Just a minute, please. ...(*Interruptions*)... Sir, I have been in this House now for 15 years. ...(*Interruptions*)... And I have not seen a single Select Committee request being passed without a discussion. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am now on a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am allowing you. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: They want to bypass Rule 124. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Please hear me out, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand Sharma, you have to read Rule 124 also. ...(*Interruptions*)... How can you ...(*Interruptions*)... I am adjourning the House for ten minutes. ...(*Interruptions*)... I am adjourning the House for ten minutes. ...(*Interruptions*)...

The House then adjourned at thirteen minutes past three of the clock.

The House reassembled at twenty-three minutes past three of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anand Sharma quoted Rule 125. I said, "Rule 124 has to be read and then only Rule 125 can be read." The position is again clear. I will read Rules 124 and 125 together. This is regarding the Bill originating in the House and transmitted to the Council. Rule 124 is about discussion. I will also read Rule 123. It says, "On the day on which the motion for consideration is set down in the list of business which shall, unless the Chairman otherwise directs, be not less than two days from the receipt of the notice, the member giving notice may move that the Bill be taken into consideration." It is 'the Bill be taken into consideration'. Then Rule 124 says, "On the day on which such motion is made -- that is today -- or on any subsequent day to which the discussion is postponed, the principles of the Bill and its general provisions may be discussed.... (*Interruptions*). Listen to me. Let me complete. That is why I asked Shri Anand Sharma to read Rule 124. It says, "...may

be discussed, but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain the principles." This means that the Bill has to be discussed, in principle, in general. So, we will not go into clause-by-clause consideration. ...(*Interruptions*)... I am only reading out what is there in the rules. Then, it says, "Any Member may move an Amendment that the Bill be referred to a Select Committee, and if such Motion is carried, the Bill shall be referred to the Select Committee." So, the procedure is, as I said, we will have the discussion and then the Select Committee Motion will be put first and the Bill Motion will be taken up, if necessary, after that. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, you are absolutely right. We have to read Rules 124 and 125 together. So, we shall only discuss the principles. Now the principle has been explained by the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the Mover moving it. But this is a general discussion.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, let me complete. In the meantime, the hon. Member has moved an Amendment that it should be referred to the Select Committee. The Amendment, that it should be referred to the Select Committee, can be discussed and then put to vote. That is the rule as per the Rules of Procedure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Digvijayaji, please, ...(*Interruptions*)... I heard all of you. Now please sit down. Digvijayaji, Rule 123 says that the Motion for the consideration of the Bill be moved. Rule 124 says that there may be a general discussion. ...(*Interruptions*)... That is what you say. General discussion doesn't mean the Minister is speaking. General discussion means general discussion by others also. ...(*Interruptions*)... You cannot say that. I don't agree. I have to give the ruling now. Then, the Motion for the Select Committee, that is, the Amendment, will be put to vote first. ...(*Interruptions*)... That is the procedure. After that, if necessary, the other Motion will be put to vote. ...(*Interruptions*)... I say, 'if necessary'. How do I know what will happen?

SHRI P. RAJEEVE: Under what rule?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is it, Mr. Rajeeve? What has happened to you? ...(*Interruptions*)... I am not listening. You sit down. I am on my legs. Mr. Rajeeve, you should know that your Motion is on an Amendment. If that is rejected,

then, I have to put the Motion to vote. Why do you say that it cannot be done? ...(*Interruptions*)... Listen to me. You may be presuming that your Motion will be carried. The problem is, you presume something. But the Chair does not presume anything. For the Chair, if the Motion for the Select Committee is rejected, then, I have to put the Motion to vote. This is what I am saying that I will first put the Motion to vote. If it is carried, ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Let the House decide by vote as to whether the Amendment should be voted now or not. Let there be a vote on that vote issue now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no procedure for that. What is this?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am really surprised over what Shri Anand Sharma said on whether to put to vote or not. We should not stick to that extent. My humble plea is, Sir, normally when a point of order or an issue is raised by a Member or a Leader or a Deputy Leader, then, the other side may have the other view. Then they also put forth their issue and then the Chair decides. Here we have seen a number of people from the same side raising the issue. I have no problem on that account also. Once that is done, it is for the Chair to give a ruling and move forward. Otherwise, we will be discussing, discussing, discussing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give the ruling.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Please give the ruling. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, what is your point?

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, let me finish.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you have anything new to say, then speak. Don't repeat.

SHRI PRAMOD TIWARI : Sir, it is new. Please read as I am reading.

"जिस दिन प्रस्ताव किया जाए उस दिन", आज प्रस्ताव किया गया है, This is the day **...(व्यवधान)...** "उसके बाद किसी दिन, जिसके लिए चर्चा स्थगित की जाए", यहां स्थगित नहीं की गई। "विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर", सिद्धांत What Misraji has said ...(*Interruptions*)... Come on this line. Sir, explain this line to me. डिप्टी चेयरमैन सर, "विधेयक के ब्यौरे पर उससे आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिए।" I repeat it. "किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिए", Just see this. Explain this line to me. चर्चा नहीं होनी चाहिए उसके आगे, This is my humble request. Even the Chair cannot misinterpret it. This is binding on the Chair and the entire House. उसके आगे चर्चा नहीं

की जानी चाहिए, जब यह बात आ गई, This cannot go beyond this. In principle this has been accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Now you sit down.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, first you explain this to yourself. "उससे आगे चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।"**...(व्यवधान)...**

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, you give your ruling.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am adjourning the House for 15 minutes or so, so that all of you can think and come back with a cool mind and then I will give the ruling. I will give the ruling without discussion after 15 minutes.

The House then adjourned at thirty-three minutes past three of the clock.

The House reassembled at forty-eight minutes past three of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I hope everybody is in cool mind. Rule 124 and 125 were quoted here. So, I need not read them here. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, हम लोग तो शुरू से कूल माइंड में हैं।**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am going to give the ruling...(*Interruptions*)...

एक माननीय सदस्य : सर, हिंदी **...(व्यवधान)...**

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): हिंदी **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : हिंदी किसके लिए? I cannot speak Hindi fluently. If I start speaking Hindi, many of you will stand up and go away. So, I should not do that...(*Interruptions*)... Now, listen...(*Interruptions*)...Rule 124 and 125 have been quoted here. So, I need not repeat them. Rule 124 says that there can be a general discussion. Rule 125 says that any Member can move a motion for sending a Bill to Select Committee and that should be put to vote. What we usually do is, we discuss and then first put the Select Committee motion to vote and then, if necessary, naturally, put the main motion. Here, I am combining both the rules and I am taking a position and my ruling is this. Because Rule 124 says that there can be a general discussion, I am allowing half-an-hour for the general discussion. Then, after half-an-hour, I will put the motion moved by

Shri Rajeeve and Shri Seelam to vote. ..(*Interruptions*)..

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: The time allotted is four hours. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Business Advisory Committee has allotted time. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Rule is clear and it says, "But the details of the Bill must not be discussed other than is necessary to explain the principle." So, I fixed half-an-hour. If you want more time, I have no problem. ..(*Interruptions*).. There can be a little more time, half-an-hour or one hour, as you please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, as far as timing is concerned, let me just clarify. I think, Mr. Deputy Chairman is right when the hon. Chair says read Rules 124 and 125 together. But in order to decide the time, please also read Rule 126. ..(*Interruptions*)..

SHRI P. RAJEEVE: Sir, can there be any discussion on the ruling? ..(*Interruptions*)..

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, ruling is not yet given. ..(*Interruptions*)..

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपसभापति जी, जब आपने रूलिंग दे दी है, तो आपकी रूलिंग आ जाने के बाद उस पर चर्चा का क्या औचित्य है? **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, अभी रूलिंग नहीं आई है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can increase the time. ...(*Interruptions*)... Let me listen to the Leader of the House. ...(*Interruptions*)... Only if the Select Committee motion is rejected, then...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, all that I am saying is, there are three stages. Stage I, when the principles and the general provisions are discussed; stage II, when the Select Committee motion takes place; stage III, when clause-by-clause consideration takes place. Except clause-by-clause consideration, the first two discussions have to take place under Rules 124 and 125. You have fixed four hours for the entire thing. Except the time required for the clause-by-clause consideration, the rest of the discussion, all has to take place under Rules 124 and 125. Therefore, adequate time for that has to be provided. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the allocated time is only two hours, but the Leader of the House says four hours and half-an-hour for this. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my point of order is simple. Once the Chair has

given his ruling and decided on half-an-hour discussion on the principles of the Bill, we have accepted the ruling. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. It is only like this. ...(*Interruptions*)... What the Leader of the House is saying is that after the discussion is over, if the Select Committee motion is not carried, then we will go to the clause-by-clause consideration. His point is that half-an-hour is not enough. That is what he is saying because more time is already allotted. But, what I have said is that there should be a general discussion in principle, according to the rules for which I said half-an-hour is enough. That is my point. ...(*Interruptions*)... Please sit down. If the House wants, you can increase half-an-hour. I have no problem.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: माननीय उपसभापति महोदय, ये चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। ये लोग किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये लोग मैरिट और डी-मैरिट पर बात करने को तैयार नहीं हैं। ये चर्चा नहीं करना चाहते। **...(व्यवधान)** ... और सर, बिजनैस एडवाइज़री कमेटी ने इस बिल के लिए चार घंटे का समय एलॉट किया हुआ है। इसमें डिस्कशन के लिए चार घंटे का समय है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The rationale of my ruling is... ...(*Interruptions*)...

SHRI BASAWARAJ PATIL: Sir, I have a point to make.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; please. Your leader has spoken. Then, what is the point? ...(*Interruptions*)... Your leader has spoken. You see, I will explain the rationale. I was agreeing that there should be a general discussion under Rule 124, and also the suggestion made from the Treasury Benches that there should be a general discussion. In principle, I agreed that. Now, then, as has been said, if the Select Committee motion— it depends, I don't know — is carried, then, all other discussion is meaningless. That is why I restricted it to... ...(*Interruptions*)... Now, listen. Please. ...(*Interruptions*)... No; listen. That is why I restricted it to half-an-hour. I was not taking away the right of the House in that. That is why I restricted it to half-an-hour. I am again saying, if that is not enough, I am ready to give it more than half-an-hour.

SHRI P. RAJEEVE: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But that is for the House to decide. ...(*Interruptions*)... That is for the House to decide. I would like the Government's view on that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we are very clear on this. We want a discussion; number one. It is also clear as per the rules, which you yourself have quoted, the principles of the Bill and its general provisions may be discussed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As necessary to explain the provisions. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am talking to the Chair. .....**(व्यवधान)...** आपको क्या प्रॉब्लम है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't do that. We are all human beings.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the sum and substance of Rules 124, 125 and 126 also...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Together I have taken. I know that. That is why I said it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Other than clause-by-clause, four hours' time is given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: And, then, accordingly, do justice, and let there be a debate and discussion. It is a discussion, not the speech by the Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agreed. I said what the hon. Leader of the House has said is a valid point. After this discussion, it is clause-by-clause. I accept that. But since for the last two hours, we are on this kind of a row, I thought, I will come to a decision in between so that both sides will agree.

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, I have one question. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; please. ...(*Interruptions*)... No, I am not allowing. I am not allowing. ...(*Interruptions*)... Please do not trouble me. You come here and do it.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, I have one question to the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; let me finish it. ...(*Interruptions*)... Let me finish. I will allow you. Therefore, I am not taking away the right of the House for a general discussion. In principle, I have agreed, what has been suggested by this side. But, as a pragmatic view, I thought, general discussion will be reduced, and put to vote. Now, I want the consent of the House. I want the Government to agree with that; half-an-hour in principle.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we have discussed issues yesterday and the

day-before also; how much time it has taken. Please understand it. My point is, if one side is having more numbers, and they say, 'no discussion at all'...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not agree with that. ...(*Interruptions*)... I did not agree with that. ...(*Interruptions*)... I did not agree with that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Four hours minus clause-by-clause, let the House be allowed to discuss it, Sir. ...(*Interruptions*)... Let the House be allowed to discuss it.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Start discussion on principle. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, our understanding is, on principles, there will be a half-an-hour discussion. Rule 126 is not invoked. That comes in, after the disposal of the amendment to refer it to the Select Committee. What we want, Sir, a clear

4.00 P.M.

understanding that once this discussion, as per your ruling is over, the amendment shall be taken up and voted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. Now, listen. I have already said, general discussion; I accept that principle, but I reduce the time to half-an-hour. By accepting the general discussion principle, I reduce the time to half-an-hour. And this side also, I do not find there is any serious objection except that ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Otherwise, we do one thing, no discussion at all. ...(*Interruptions*)... No discussion, no opportunity to the Government, no opportunity to the Minster ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, half-an-hour...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: What is this? Let them have whatever they want to do. ...(*Interruptions*)... Let them do whatever they want to do, Sir. ...(*Interruptions*)... Sir, half an hour discussion was a discussion for two hours. Short notice discussion was a discussion for three hours. Let me say that with all my command. With this experience, half-an-hour discussion was a discussion for two hours. Short Notice Discussion was a discussion for three-and-a-half hours, four hours also depending on the importance of the issue. Here is a Bill, and the Bill is very clear. You must give adequate time. I am not able to understand why they have any objection at all. What is the problem? What is the problem in discussing? Normally, the ruling party says, less time and Opposition asks for more time. Now, here is a situation, where opposition is asking for less time and ruling party is asking for more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should appreciate that. You should be happy

with that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Why? We want the people of India to know what are there in this provision. It is not on principles, it is on provisions of the Bill also. Provisions of the Bill and principles also, both will be discussed. So, my suggestion is, the Chair has to protect the interest of the House. Keeping that in mind, the country wants a debate and discussion on issues. Please allow, please allow three hours... (*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, यह पहली बार हो रहा है **...(व्यवधान)...** सर, यह सदन के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। **...(व्यवधान)...** यह अपने आप में इस सदन के इतिहास की पहली घटना होगी कि सत्ता पक्ष तैयार है चर्चा के लिए और विपक्ष कह रहा है कि बिना चर्चा के बिल को पास करो या फिर फेल करो, यह आपके हाथ में है। **...(व्यवधान)...**

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, at the moment, the very fate of the Bill is hanging. We are not sure. The entire opposition is not speaking on the principles of the Bill. What hon. Members are saying is that "we need, two hours, three hours, four hours". Yes, two hours, three hours, four hours, it would definitely take, provided there is participation from the entire House. But, as far as, I understand, and which is the understanding I have been given by my friends from the entire Opposition, none of them is going to speak till the Select Committee Amendment is voted ... (*Interruptions*)... Then, in such a case, half-an-hour is more than enough.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, when we were having discussion, you were kind enough to observe that after the discussion is over, first you will go for voting on the Select Committee. We don't know what will happen and thereafter, you will get voting on the Bill. Therefore, I am only saying what you have repeatedly observed. Now, the sanctity of any Bill is, discussion is of essence. Surely, they will also say that you should go for the Select Committee and they will point out the loopholes in the Bill to insist for its reference to the Select Committee. We will show the merit of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, they are not doing.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: How can half-an-hour be enough for it? Therefore, I would again request you, let the proper three-four hours, as assigned, be allowed and then voting take place.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, see...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, अभी तक बारह-तेरह सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए नाम दिए हुए हैं। **...(व्यवधान)...** इन बारह-तेरह सदस्यों के अलावा तेईस और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** तो बारह-तेरह सदस्यों के नाम अभी चर्चा के लिए हैं। तेईस और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** सर, आप सदस्यों के इस अधिकार की रक्षा कीजिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, I think this side and the entire this side, they are saying they are not speaking at all. That means out of two hours, half-an-hour is enough and we will discuss. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I find the comments made just now, the observation made by the Leader of the Opposition have actually given the game away. ...(*Interruptions*).. Of course, it is a game. ...(*Interruptions*).. It is a game being played with the country. ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सरकार भाग रही है**...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य : आपकी सच्चाई सामने आने वाली है**...(व्यवधान)...**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : आप लोग बैठिए**...(व्यवधान)...**

SHRI ARUN JAITLEY: The Leader of the Opposition says, 'on merits, we have nothing to say on this Bill. Therefore, we only want to obstruct the progress of this country.' ...(*Interruptions*)... What do you have to say on the provisions and principles of the Bill?

श्री आनन्द शर्मा : बिल्कुल गलत **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... Let me proceed. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*).. All of you please sit down. ...(*Interruptions*)... Except the Leader of the House, all of you sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we would like to be enlightened by the Leader of the Opposition. ...(*Interruptions*)... What does he have to say that the right of the States is going to be affected, the right of the tribal States is going to be affected? ...(*Interruptions*)... He has nothing to say on this. ...(*Interruptions*)... It exposes this fact. ...(*Interruptions*)... Therefore, he says that they do not want to speak on the subject. ...(*Interruptions*)... राज्यों के अधिकार छिन जाएंगे, आप लोग उस पर बोलने को तैयार नहीं हैं**...(व्यवधान)...**पहली अप्रैल से लाखों मज़दूर, जो इन खानों में काम कर रहे हैं, वे बेरोज़गार हो जाएंगे, आपके पास कुछ कहने को नहीं है**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please sit down. ...(*Interruptions*)... No

more further discussion. ...(*Interruptions*)... No more further discussion. Half-an-hour general discussion is for those who want to speak. I think nobody from this side is speaking. ...(*Interruptions*)...

Who want to speak they come from this side. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, यहां जो माननीय सदस्य हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। लगभग 12 सदस्यों ने नाम अभी दिए हुए हैं। कुछ और सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे इस सदन में नहीं है जो यह कहे कि हम इस सदस्य की जिम्मेदारी लेते हैं और यह नहीं बोलेगा। इसलिए जिन सदस्यों ने नाम दिए हुए हैं, उनके नाम बुलाए जाएं तथा और भी जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naqviji, three-and-a-half hours is for the Bill. If the Motion for Select Committee is carried only, then it will go, otherwise, ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: What you are doing is giving half-an-hour for discussion and three-and-a-half hours for clause by clause, which has never been done. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you are not only the Deputy Chairman, you are the custodian of the House too. Members want more discussion. The time allotted is four hours and now it is being curtailed to half-an-hour. Sir, can the principles and provisions be discussed in twenty seven or twenty eight or thirty minutes? ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... They do not want to discuss this matter. ...(*Interruptions*)... Sir, Ghulam Nabiji has said that they do not want to speak. It is their choice. We cannot force them. I do agree that we cannot force them. Nobody can force other Members to speak. But the only thing is that when Members are interested, the Minister is interested to explain to the country about the provisions, about the principles, about the advantages, about the problems being faced by the people, they must be allowed. For the first time in the parliamentary history of India, such a thing is happening. We are not able to understand this. What is the logic? ...(*Interruptions*)... What is the logic? If somebody can explain this, we would be happy to understand it. ...(*Interruptions*)... Clause-by-clause is always for half-an-hour. ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आपके मंत्री ने ही समय दिया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाओ। ...**(व्यवधान)**... Hon. Members, please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down, please. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down, else I will have to adjourn

the House. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down, please. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, the House works on...(*Interruptions*)... The democracy works on...(*Interruptions*)... Please...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... The democracy works on the principle of give and take. It works on the principle of...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, the democracy works on the principles of give and take. This side may have majority or that side may have majority. It happens. But, it is for us to solve the problem. I wanted, as far as possible, a consensus. That is what I was trying. I have been trying that all through. But despite two hours' efforts, I have not been able to succeed in that. It is my failure. I admit that. But, do you want a deadlock? Do you want a deadlock? Are we not here to solve this problem? That is why I gave a via media. Everybody knows that if a motion for Select Committee is carried – Najmaji is here; she knows the rules much better than I – then the Bill cannot be discussed here further. It will go to the Select Committee. ...(*Interruptions*)... Please listen to me. ...(*Interruptions*)... Please listen to me. ...(*Interruptions*)... It will go to the Select Committee. ...(*Interruptions*)... I will come to that. ...(*Interruptions*)... I will allow you. That is why I mentioned your name. ...(*Interruptions*)... Everybody knows that if the motion to send it to the Select Committee is carried, then, the discussion will stop here. That is why I thought it prudent to have voting after half-an-hour. ...(*Interruptions*)... That was my point. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, in your earlier comment, you asked why we should presume. Now, you yourself are ...(*Interruptions*)... What to do? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not presuming. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, rule 125 comes after rule 124. ...(*Interruptions*)... Rule 125 comes after rule 124. आपने भी कहा, the Chair also said it and we are also saying the same thing. Rule 124 provides an opportunity for a discussion on the provisions and the principles. Please allow the discussion. Then, subsequently, the Motion for sending it to the Select Committee will also be taken. If they have the numbers, they can...(*Interruptions*)... But, why is the opportunity of the Members, particularly from the ruling party, and the Minister is being curtailed to have their say on such an important issue that concerns millions of people, particularly the tribals and the poor people. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Sir, you mentioned my name. ...(*Interruptions*)... You have mentioned my name and

that is why I want to say this. They have a viewpoint. You have agreed to have a discussion for half-an-hour for them to oppose it, to send it to the Select Committee or whatever it is. But, what about us? We want to discuss the Bill. ...(*Interruptions*)... They may not be willing to discuss. But we have a right to have a discussion. ...(*Interruptions*)... If they want to oppose, they can. But, we want to discuss the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, the issue is very simple. You have given the ruling. Now, the point is that there is no objection from any side that under Rule 124 or 125, the issue should be discussed, and, then, the Motion has to be put to vote. The question is, as you rightly said, Sir, that the amendment will have to be moved. That is the procedure. Nobody should make an objection to that. When an amendment is moved, first, the amendment is taken up for voting. The question now is of the discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, you have given the ruling. ...(*Interruptions*)... I am in the House from 2000. ...(*Interruptions*)... I am very sorry to say that. ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: So what? ..(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The Deputy Chairperson ... (*Interruptions*)...

SHRI K. RAHMAN KHAN: I have not said anything. ...(*Interruptions*)... I am not saying anything. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: In 15 years, I have not heard like this... (*Interruptions*).. There is always a discussion on the motion for Select Committee ...(*Interruptions*)... No, sorry. I have heard you. What you are saying is wrong. ...(*Interruptions*)... I have to interrupt you.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Why are you shouting? ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Never a Select Committee amendment has been done without a debate. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for 30 minutes.

The House then adjourned at seventeen minutes past four of the clock.

The House reassembled at forty seven minutes past four of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I am starting the discussion. From Congress, nobody is speaking, as has been informed. Shri Tarun Vijay; not present.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, एक विषय है। आपने कहा कि आधे घंटे में पूरी चर्चा खत्म करनी है। इस पर लगभग 13-14 सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं। हमारी पार्टी से कुछ लोग हैं, कुछ और भी सहयोगी दल हैं तथा कुछ बहुत ही विद्वान और महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कि गांव, गरीब, किसान और झुग्गी-झोंपड़ी के इंसान की समस्याओं के प्रति चिन्तित हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)... Please, please. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: अगर मान लीजिए, कांग्रेस के मित्रों को देश के आदिवासियों और देश के गरीबों के हितों के बारे में कुछ नहीं कहना है, तो हमें कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन जो उनका समय है, उनके समय में हम उनके जैसी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके हितों की बात कहेंगे। **...(व्यवधान)...** यह सभी के हितों की चर्चा है, इसलिए उसको स्ट्रिक्ट मत करिए।**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will have your time. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उसको स्ट्रिक्ट मत करिए।**...(व्यवधान)...** इस पर सभी बातें होनी चाहिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I have agreed ... ...(*Interruptions*)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मुझे एक चीज़ क्लियर करने दीजिए।**...(व्यवधान)...**

†قائد حزب اختلاف (شری غلام نبی آزاد) : سر، مجھے ایک چیز کی وضاحت کرنے دیجئے (مداخلت)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ऐसा नहीं है कि इधर से लोग नहीं बोलना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** इधर से भी लोग बोलना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** हमने सोचा कि अगर इसको जल्दी dispose of करना है, उसके लिए **...(व्यवधान)...** वरना हमारे लोग भी बोलना चाहते हैं।**...(व्यवधान)...**

†قائد حزب اختلاف (شری غلام نبی آزاد) : ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے لوگ نہیں بولنا چاہتے ہیں...(مداخلت)...

ادھر سے بھی لوگ بولنا چاہتے ہیں۔ ...(مداخلت)... ہم نے سوچا کہ اگر اس کو جلدی ڈسپوز آف کرنا ہے،

اس کے لئے ...(مداخلت)... ورنا ہمارے لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں ...(مداخلت)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): सर, **...(व्यवधान)...** हम सब अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** सर, हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...**

---

† Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, you have 14 minutes. ...(*Interruptions*)... Mr. Naqvi, please sit down. ...(*Interruptions*)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): सर, **...(व्यवधान)...** यह अच्छी शुरुआत नहीं है। **...(व्यवधान)...** यह अच्छी शुरुआत नहीं है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Tarun Vijay, please. ...(*Interruptions*)... Mr. Tarun Vijay, please. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, आप पहले समय बढ़ाइये। **...(व्यवधान)...** आप पहले समय बढ़ाइये। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun Vijay, please; absent. ...(*Interruptions*)... Next is, Shri Basawaraj Patil. ...(*Interruptions*)... Shri Basawaraj Patil. ...(*Interruptions*)...

SHRI BASAWARAJ PATIL: Sir, I am here. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: ठीक है। आप बोलना शुरू कीजिए। **...(व्यवधान)...** श्री अनिल माधव दवे। **...(व्यवधान)...** Others can sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, **...(व्यवधान)...** इस पर चार घंटे का समय निर्धारित है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil Dave. ...(*Interruptions*)... You please start. ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, अगर वे नहीं बोलना चाहते हैं, तो उसका मतलब यह तो नहीं कि समय कम कर देंगे। **...(व्यवधान)...** समय तो चार घंटे का है। दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil Dave, please start. ...(*Interruptions*)... Mr. Anil Dave, please start. श्री अनिल माधव दवे।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित है, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलना चाहती है, तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि समय कम करेंगे। **...(व्यवधान)...** समय तो चार घंटे का है, इसलिए दूसरे को मौका देना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: अनिल माधव दवे, कृपया आप शुरू कीजिए।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, जैसा कि बिल को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा कि यह देश की रोजगार और उत्पादकता का दूसरा **....(व्यवधान)...** सर, माइक चालू नहीं है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is speaking. ...(*Interruptions*)... Nothing else will be allowed. ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : सर, माइक चालू नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री नरेश अग्रवाल: डिप्टी चेयरमैन सर, आधे घंटे का टाइम है और सिर्फ बीजेपी को 40 मिनट! **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... वह तो चेंज हो जाएगा। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, अब चर्चा शुरू हुई है, तो नरेश अग्रवाल जी का भी बोलने का मन कर रहा है। आप भी बोलिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please. ...(*Interruptions*)... Mr. Anil Dave. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : उपसभापति जी **...(व्यवधान)...** सर, माइक नहीं चल रहा है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is the mike not working? ...(*Interruptions*)... देखिए, क्या हुआ। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, हाउस adjourn कीजिए, क्योंकि mike is not working. ...**(व्यवधान)**...

श्री अनिल माधव दवे : सर, आगे वाला माइक ऑन हो गया, लेकिन मेरा माइक ऑन नहीं हुआ। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, थोड़ी देर के लिए हाउस adjourn करके technical fault को ठीक करा लिया जाए। **...(व्यवधान)...** ऐसे में चर्चा नहीं होगी। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All of you, please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, इन्होंने अपने पुराने अनुभव लगा कर जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनके माइक को ही डिस्टर्ब कर दिया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil Dave. ...(*Interruptions*)... Check up his mike; what is the problem? ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : सर, मैं बगैर माइक के कैसे बोलूंगा? **...(व्यवधान)...** मेरा गला फट जाएगा। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, माइक तो ठीक कराना पड़ेगा। माननीय सदस्य कैसे बोलेंगे? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: माइक को जल्दी ठीक किया जाए। **...(व्यवधान)...** Now you may speak. ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : सर, माइक नहीं चल रहा है। **...(व्यवधान)...** सर, मैं आगे आकर बोल सकता हूँ। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may come to a place where the mike is working. I am permitting you to speak from another seat. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, इसमें जो technical गड़बड़ी है, उसको ठीक करा दीजिए। इसको correct करा दीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: अब माइक ठीक हो गया। अब आप बोलिए।

श्री अनिल माधव दवे: उपसभापति जी, आज मेरी लाइन जमने नहीं दी जा रही है। जैसा कि कहा गया था कि इस देश में रोजगार और उत्पादन देने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वह कृषि है और उसके बाद दूसरा बड़ा जो संसाधन है, जो बहुत लंबे समय से, कई सालों से जब दुनिया को लोहा पैनाना नहीं आता था, लोहे का उपयोग करना नहीं आता था, उस जमाने में हम सोना खोदते थे, सोने का प्रयोग करते थे, आयरन ओर खोदते थे और उसका इस्पात बनाते थे। हमारे देश के अंदर खनिज एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और पिछले 65 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमने उसका दोहन किया है, वह वस्तुतः शोषण है। मैं शोषण इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि उसका लाभ वहां के रहने वाले

[श्री अनिल माधव दवे]

वनवासी और जनजाति के लोगों को प्राप्त होना था, जो कि उसके मूल मालिक हैं, वह उनको न प्राप्त होकर मुट्ठी भर चंद लोगों को प्राप्त हुआ, जिसके कारण देश का नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ और महँगी चीज़ें सस्ती दरों पर जाती रहीं। लेकिन, इस सरकार के आने के बाद, मैं यूपीए की पुरानी सरकार के उन विषयों पर नहीं जाना चाहता कि उनके ऊपर सीएजी ने क्या कहा था। वे सारी बातें हम सबकी रटी हुई हैं, कंठस्थ हैं और नींद में भी हमें उसी के सपने आते हैं। ...**(व्यवधान)**... इसलिए हम सबको उसके फिगर्स याद हैं, सारी चीज़ें याद हैं। लेकिन, यह सरकार जो आई है, जो मोदी जी की सरकार है, इसने आने के बाद सबसे पहले यह कोशिश की कि जो खनिज है और उसका जो पहला मालिक है, उसके बारे में इसने यह डिफाइन किया कि वह वनवासी है, वह गाँव का व्यक्ति है, वह मजदूर है, जो वहां रहता है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए उसकी मालिकियत पहली है और वह मालिकियत उसे दी जानी चाहिए।

माननीय उपसभापति जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इतना सुंदर संविधान दिया। ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, बाबा साहेब ने जो संविधान दिया, वह इतना सुंदर और अच्छा था, जिसके अंदर सबको न्याय मिलने की पूरी सम्भावना थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने वालों ने न्याय करने के स्थान पर वैसा न्याय नहीं किया जैसे न्याय की आवश्यकता थी। यही कारण है कि 65 वर्षों के अंदर हम उस बात को प्राप्त नहीं कर पाए और उसको प्राप्त करने के लिए ही यह पूरा प्रयत्न इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है कि चाहे झारखंड हो, पश्चिमी बंगाल हो, ओडिशा हो या देश के अन्य वे सारे राज्य हों, जहां वे सारे खनिज, वे सारी खदानें थीं और विशेषकर महत्वपूर्ण खनिज और कोयले की थीं, उन सारी की सारी खदानों की जो मालिकियत है, वह उसके किसानों को, उसके मजदूरों को, वहां के वनवासी लोगों को, शेडल्यूल्ड ट्राइब्स को मिले। इस बिल के माध्यम से सरकार वह मालिकाना हक़ उनको दिला रही है। वह यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सीधे राज्यों तक जाए, राज्यों के विकास में प्रयोग हो और विशेषकर उन जिलों के अंदर उसका प्रयोग हो, जिन जिलों के अंदर उसका स्थान है। लेकिन, अगर हम कोशिश करते हैं कि यह बिल आगे जाए, तो अभी 32 खदानों के अंदर ही हमें 300 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है। ...**(व्यवधान)**... दो लाख की ऐडिशनल आय और हो रही है। इन सबको मिलाकर अगर आप इसका एक दिन का भी ब्याज गिनेंगे तो मुझे लगता है कि उस एक दिन के ब्याज से एक दिन की संसद चल सकती है। इतनी जो आय हो रही है, वह आय भी उनको ही जाने वाली है। अगर यह आय आज से 15 दिन बाद होगी, एक महीने बाद होगी, छः महीने बाद होगी, तो उसका जो नुकसान होने वाला है, वह उस वनवासी का होने वाला है, मेरा और आपका नहीं होने वाला है। यह नुकसान उस वनवासी का है, यह उस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का है, उस किसान का है, उस सीमान्त किसान का है, जो वहां रहता है और वहां जो खदान है, वह उसकी है, लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? तो हम प्रोसिज़र को लेकर बैठे हैं। क्या विषय है? तो प्रक्रिया चल रही है। भाई, आपकी प्रक्रिया चल रही है, इसके आधार पर ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं रोकी जा सकती? आपकी प्रक्रिया चल रही है, इसके कारण देश पर जब हमला हो रहा हो तो उसका जवाब देना तो नहीं रोका जा सकता? आपकी प्रक्रिया चल रही है तो शांति

और विकास के कार्यों की यह यात्रा तो रोकी नहीं जा सकती? इसको रोकना अपने आप में उतना

5.00 P.M.

ही बड़ा अपराध है, जितना कोई देश हम पर हमला करे और हम जवाब न दें और हम कहें कि इसके लिए हम कोई प्रक्रिया करना चाहते हैं।

मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया विकास के कार्यों में जहां डेवलपमेंट इश्यु है, जहां विकास है और उस विकास की जिसको जितनी आवश्यकता है, उससे पूछो जिसको रोटी नहीं मिलती, उससे पूछो जिसको पानी नहीं मिल रहा है। अटल जी कहते थे कि अगर हो सकता है तो सबसे पहले एक काम करो कि इस गांव को पीने के लिए शुद्ध पेयजल दे दो। उस गांव के अंदर जब पीने के लिए पेयजल नहीं मिलता है तब समझ में आता है कि मिनरल वॉटर लेकर हम तो स्कार्पियो में घूमते हैं लेकिन वहां का वनवासी, वहां का ग्रामीण उसी पानी को पी रहा है। इसलिए विकास के कामों के अंदर मुझे लगता है कि प्रक्रियात्मक कोई विषय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जितने राजनीतिक विषय हैं, कुछ विषय ऐसे हैं कि जो राजनीति से परे होकर के, उनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। आज हम देश की बेरोजगारी से भी लड़ रहे हैं और इस बेरोजगारी से लड़ते समय हम नहीं चाहते कि खदानों को बंद करके हम और बेरोजगार खड़े कर दें। आवश्यकता है कि खदानों के उत्खनन से होने वाली आय के कारण ज्यादा रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। मेरा कहना है कि वह रोजगार उसी प्रांत के लोगों को पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वे पीड़ित रहे हैं, 65 वर्षों के अंदर उन्हें वह नहीं मिला, जो उनको मिलना चाहिए था। अपनी बात को विस्तारित करते हुए मिनरल्स के अंदर यह जो बिल है, यह बिल हमारे विकास का बहुत बड़ा पत्थर है और इस बिल के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर 32 खदानों से इतनी आय प्राप्त हो रही है, अगर इन सारी खदानों से हमको इतना मिल रहा है तो आप सिर्फ कल्पना करिए कि पूरी की पूरी ठीक से हो गई और अगर हमने सारा कर लिया तो उसके कारण हमारे पास कुल कितना लिक्विड फंड खड़ा हो जाएगा और उसके कारण हम विकास के कितने कामों को गति दे सकते हैं। जो लोग उड़ीसा नहीं गए हैं, जिन लोगों ने दूरंत क्षेत्रों के अंदर उन क्षेत्रों को नहीं देखा है, वे जाकर के देख लेंगे तो ध्यान में आ जाता है कि इन कामों को नहीं रोका जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के अंदर जब भी कोई रोड़ा अटकाएगा तो वह कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होना है, बस इतना ही होना है कि वह वनवासी, वह ग्रामीण, वह गरीब, वह पिछड़ा जिसके लिए हमने 1972 के अंदर नारा दिया था "गरीबी हटाओ", हमने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे और गरीबी हटाने के लिए जिसको जितने प्रयत्न करने थे, उन्होंने किए। मैं यह नहीं कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**... आप हर बात का पॉलिटिलाइजेशन प्लीज, मत करिए। आप 65 साल तक कर चुके हो और भुगत चुके हो। कुछ मामले छोड़ने पड़ेंगे। मैं ही सबसे पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि गंगा के लिए राजीव जी ने इतने पैसे दिए थे और आज मैं 1972 की बात कर रहा हूं। लेकिन वह नहीं मिटी तो उसका कारण, जवाब आपको भी देना है और मुझको भी देना है, क्योंकि अगली पीढ़ी डिविजन करके जवाब नहीं मागेगी, अगली पीढ़ी संयुक्त रूप से पूछेगी कि संसद क्या कर रही थी? इसलिए संसद को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ। ...**(समय की घंटी)**... अगर गरीबी नहीं हटी है तो क्यों नहीं हटी? ऐसे बहुत सारे विकास के बिन्दु हैं जिन विकास के बिन्दुओं के ऊपर...**(व्यवधान)** ...**(समय की घंटी)**... सर, बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिला है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take two more minutes only.

श्री अनिल माधव दवे : उपसभापति जी, जब से यह सरकार आई है, यह आई ही इस मुद्दे पर थी कि अच्छे दिन आएंगे। **...(व्यवधान)...** आज अच्छे दिन लाने की कोशिश हो रही है तो आप लाने नहीं देना चाह रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, गरीब को गरीब बनाए रखो। आप कह रहे हो कि मजदूर आदमी जो शाम को ढाई सौ, तीन सौ रुपए कमाता था वह बेरोजगार हो जाए। यह होने वाला नहीं है। आदिवासी के बदन पर कपड़े रहेंगे। जितने कपड़े मेरे और आपके बदन पर हैं उतने सारे कपड़े उस वनवासी के बदन पर भी होना चाहिए। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में उसके बच्चे भी पढ़ने चाहिए। जिन अस्पतालों में हम ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती होते हैं उनमें वे भी आने चाहिए। जिन बिजनेस क्लास के अंदर और अच्छी एयरलांइस में हम घूमते हैं, उनमें जाने का अधिकार उसका भी है और उसका अधिकार अगर आप छीनेंगे तो वह तो नहीं होने दिया जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dave, please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि विकास की इस यात्रा में मैं वीर सावरकर के एक वाक्य को बोलना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't make such unnecessary noise. Don't do that. ...(*Interruptions*)...

श्री अनिल माधव दवे : एक वाक्य बोलना चाहता हूं। "अगर साथ चलो तो ठीक, विरोध करो तो ठीक, नहीं चलो तो ठीक।" देश का विकास होकर रहेगा, अच्छे दिन आकर रहेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I will take just four minutes to make four points. Sir, the basic thing which we are saying is we want to make some constructive suggestions. The first one is the extension of the areas of mining and the second one is on clauses 18 and 20 where this Government has made a lot of statements about cooperative federalism. ...(*Interruptions*)... No, no; I am just making three points. ...(*Interruptions*)... Allow me to make my three points. ...(*Interruptions*)... The point which we want to make is, in all this please take the State Governments into confidence; please work it out in such a way where the State Governments will not be harassed, will not be run over. If this can be assured by the Government, we have no issues on that point on going along with this Bill. But this needs to be addressed because the State Governments have to be taken into confidence. However, in clause 18 and in clause 20, there is some issue on that.

Then, we come to the District Mineral Foundation and the National Mineral Exploration. That overall is a good idea, but you have not told us in detail how this will

be organized, what is the organizational structure. Our constructive suggestion for this is, please consider putting this in the rules so that we all know how that is going to be constructed or how that is going to be made up. In fact, on that point, there is an issue of welfare of the tribals, and there is no doubt that this has to be addressed in the most serious manner possible. If there is a way, in the DMF, should we have the adivasis, the tribals? Should they have a decisive management in that DMF so that they feel that they are part of this? These are constructive suggestions. From Trinamool, you will get constructive suggestions. We are not going to sit here and oppose, oppose and oppose. We are opposed to certain sections of this. ..(*Interruptions*).. We are opposed to certain sections. We have issues on the way you handled federalism. We have other bigger issues on how you handled the communal issues in the country. We are telling you to tread carefully on federalism. Please take the States into confidence. You are doing a lot of talk about federalism. Once we see that that talk comes into action on the ground, we will be with you. But we have to be very, very careful to see that you don't run roughshod over the States. The *adivasis* is a big issue. We have given you a concrete, solid, actionable way where you can get around them because 40 per cent of those mining districts are inhabited by *adivasis*.

The last one is an ecological point. On the ecological point, we have not addressed the closure of mines which the UPA-II had done very well in the 2011 Bill. It is a very open-ended question on the closure of mines, and once the mines don't shut down then there are sustainable development issues, there are ecological issues. I urge the Government to address these issues; address them quickly in the best way you can. Trinamool is always there to provide constructive opposition. We will continue to do that. Thank you.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, the Mines and Minerals Amendment Ordinance is, I think, a step in the right direction because the natural resources must be protected at any cost. So far so much of illegal mining and exploitation has taken place. Now, everything must be done in a transparent manner and for that purpose, the Bill is now brought by the Government. I am of the humble view that the Government is moving in the right direction to benefit the States, the nation and the general public. Thank you, Sir.

SHRI KALPATARU DAS (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, this Bill is very, very important for the country and, especially, for Odisha. We have seen in the past that whatever royalty was due for State, it was not being increased. We have seen UPA Government demanding, time and again, for revision of royalty. Though it is to be revised every three years, it was not revised for years. During this period, scams like illegal mining, favoritism, nepotism and grant of lease, stoppage of mining operation

[Shri Kalpataru Das]

resulted in closure of some industries and fall in the production of industries. The State has suffered a lot. We do not support all the clauses of the Bill. We also have our reservations. We want to protect the interests of the mineral-bearing States. We want to discuss the matter and give some suggestions on how the interests of the States can be protected. My State is the owner of minerals. States grant the mining leases, the mining concessions, but the States are not being consulted while preparing the Bill, while trying to pass it in the House. The entire country and, especially the people in mineral-rich States like Odisha, Jharkhand and West Bengal are waiting how the interests of the States will be protected. So, on this ground, we want to discuss the matter. Whatever is possible, the procedure is there. Anybody can seek division at any stage; during amendment, during Select Committee. That will be there. But this Bill has to be discussed and a decision has to be taken. Unless this is done, from 1st April, what will be the state of affairs in the country? All the mines will be closed. Industry will be closed. Exploitation will be done. What will be the fate of lakhs of labourers working in the mining sector? So, every Member of this House has a right to suggest. They can convince the Government to effect some amendment to protect the interests of the States. That is why I, on behalf of the Biju Janata Dal, want that this Bill should be discussed in the House.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister. The objective behind the Bill clearly envisages the intent and the direction in which the Government wanted to move. The objective also indicates how it was able to streamline the coal mining and, in the same way, it also wanted to streamline the mines and mineral sector which contributes nearly two per cent of the GDP. There is no doubt that this sector is in shambles. Secondly, there are many positive aspects of the Bill, be it relating to hassle-free long lease period or be it auction of mines and mineral blocks which generate additional revenue to the States and Centre or setting up of District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust to help the displaced and affected people due to mining operations or setting up of special courts or increasing penal provisions. Sir, I welcome the creation of District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust created out of contributions from mining leaseholders under clause 9 which proposes to add a new Section 9A in the principal Act. The fund so generated from the leaseholders will be spent for the interests and benefits of the people and areas affected by mining and also tribal area people. I welcome the constitution of special courts by the Government by amending Section 30 of the parent Act. It is good that the Government has given powers to States to set up special courts to redress the grievances, with powers of Sessions Court. But the cash-strapped States will find it difficult to set up such courts

as we have seen how, after Government of India stopping funds to Fast Track Courts, States have also washed off their hands and ultimately how they are discontinued. I request that some financial assistance for setting up Special Courts be given by the Government of India, so that they are established and run as per the expectations.

Sir, my State of Telangana is famous for rich minerals. Our State has so many minerals like iron ore, manganese, limestone, quartz, barites, etc.

Sir, 13th Schedule to the AP Reorganisation Act mandates setting up of an integrated steel plant at Bayyaram. Today, a three-million-tonne per annum capacity steel plant generates direct employment for 3,000 workers and indirect employment for 15,000-20,000 people. I am sure Bayyaram can be of that size. So, it has to be expedited. There are estimated 11 million tonnes of uranium deposits in Nalgonda which Uranium Corporation of India has started exploring. We have so many minerals in other districts, namely Nalgonda, Ranga Reddy, Karimnagar and Adilabad which are catering to the needs of cement industry. We also have manganese ore in Adilabad. Now these have been notified under 4th Schedule as Notified Minerals.

The Bill definitely helps Telangana not only in getting higher revenue but also in eliminating allocation of mines at one's discretion and putting in transparent auction in allocation of mineral resources. Secondly, increase in the tenure of mineral leases from 30 to 50 years under clause 7, which proposes to amend Section 8 of the parent Act, has been the demand of the industry. It will definitely help them as they are facing problems of subsequent renewals. As the hon. Minister and the House are aware, in the last few years a large number of mining leases were given which have fallen substantially not only due to court cases but also due to other reasons coupled with problems in lease renewals resulting in dependence on imported minerals.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, with these words, I support the Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Ashok S. Ganguly. Are you speaking?

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Sir, I had a number of issues that I wish to raise. But in view of what has happened in the last few hours and given the fact that you have laid down your ruling, I would say this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take 4-5 minutes.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: माननीय उपसभापति महोदय, कृपया आप हर सदस्य से यह न पूछिए कि आप बोलना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से आप पूछ सकते हैं कि वे बोलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अन्य सदस्यों के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए जो सदस्य नहीं बोलना चाहते हैं, वह ठीक है, लेकिन जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें कृपया समय दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. बोलिए, बोलिए। Please speak.

DR. ASHOK S. GANGULY: The discussion that might have taken place on the details of the Bill clause by clause would have permitted more surgical debate, because there are a lot of very good points. But there are a lot of apprehensions regarding the Bill. Since that debate seems unlikely given the mood in the House and what has been going on for the last few hours, I do not know whether I am going to add value to it by taking up the time of the hon. Members. So, I forgo my privilege of commenting on this Bill by saying that I reserve my right to express my views and apprehension when the time is appropriate to do so and when it will be far more productive than my taking the time of this House now. Thank you, Mr. Deputy Chairman.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anil Desai, not here. Shri Ramdas Athawale.

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं पहली बार राज्य सभा में आया हूं। मुझे लगता था कि लोक सभा से यह हाउस बहुत उच्च लैवल का है। लेकिन यहां लोक सभा से भी ज्यादा गड़बड़ देखने के बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं दोबारा लोक सभा में चला जाऊं। ठीक है, यहां सब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, यहां सब intellectual लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं और पूरा देश देख रहा है कि हम यहां किसलिए आए हैं। यह विधेयक कोयला खानों में जो illegalities चल रही थीं, उसको legalise करने के लिए या जो ट्राइबल एरिया है, जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर या गढ़चिरौली है, तो कोयला माइन्स ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, मैं इतना ही बताना चाहता हूं-

"कोयले का रंग ज़रूर होता है काला,

लेकिन वह होता है विकास की माला।

कोयला खान को अगर लगा देंगे ताला

तो * " ...**(व्यवधान)**...

कुछ माननीय सदस्य : सर, यह गलत है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री रामदास अठावले : इसलिए मेरा इतना कहना है कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, इन्होंने जो * कहा है, this is unparliamentary and this should be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is unparliamentary and it is expunged. रामदास जी बोलिए।

श्री रामदास अठावले : महोदय, ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनको अधिकार देने के लिए **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't do that. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : यह बहुत इम्पॉर्टेंट बिल आया है, इसलिए आप लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए, इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए। आप चर्चा करने के लिए यहां आए हैं, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट बिल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप सपोर्ट करें या विरोध करें, वह भी आपको अधिकार है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि चार घंटे की चर्चा को आधे घंटे में खत्म करो। जब आपको चर्चा करनी होती है, तो बोलते हैं कि छः घंटे चाहिए और अभी आप बोल रहे हैं कि आधे घंटे में खत्म करो, तो आधे घंटे में चर्चा कैसे खत्म हो सकती है? **...(व्यवधान)...** यह बहुत बड़ा विषय है। मेरा कहना है कि ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को न्याय देने की कोशिश आपने भी की थी। आपने 60-65 साल तक कोशिश की, अब हमें मौका मिला है। पहले मैं उधर ही था, लेकिन अब इधर आया हूं **...(व्यवधान)...** इसलिए आदिवासियों को न्याय देने के लिए अगर यह बिल लाया गया है, तो सभी लोगों को इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। आदिवासियों को न्याय देने के लिए, इल्लीगल माइनिंग का जो काम चल रहा है, उसको रोकने के लिए अगर यह बिल आया है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

कुछ माननीय सदस्य : कौन सा बिल? कौन से बिल पर बोल रहे हैं आप? **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावले : अगर हम गलत काम करेंगे, तो पांच साल के बाद जब हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो बताएंगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर अभी हमें मौका मिला है तो **...(व्यवधान)...** नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे दिन देश में आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आपके लिए नहीं हैं, हमारे लिए और लोगों के लिए अच्छे दिन लाने हैं। **....(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't comment while sitting. ...(*Interruptions*)... Please don't do that. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : जब हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो हम लोगों के लिए अच्छे दिन लाएंगे। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, तो जो आपका हाल हुआ, वही हमारा होने वाला है, इसलिए हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। महोदय, यह बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर आज तीन-चार बार

---

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री रामदास अठावले]

हाउस एड्जॉर्न हुआ, यह अच्छी बात नहीं है। उपसभापति महोदय, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप उधर के हैं, लेकिन आप उनको भी ठीक करते हैं और हमको भी ठीक करते हैं, इसलिए आप जैसा शेर होना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : दोनों ही ठीक नहीं होते हैं।

श्री रामदास अठावले : आप हर हालत में हाउस चलाने की कोशिश करते हैं। यह बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि यह बिल कितना इम्पॉर्टेंट है। **...(व्यवधान)...**

कुछ माननीय सदस्य : कौन सा बिल?

श्री रामदास अठावले : इसलिए इस बिल के इतना इम्पॉर्टेंट होने की वजह से **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't do that. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : हम इस बिल का समर्थन करते हैं और इस बिल के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा, आदिवासियों को न्याय मिलेगा **...(समय की घंटी)...** यह हम आशा करते हैं, जय भारत!

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मुख्तार भाई, रामदास जी का नाम ज़रा मोदी जी के पास भिजवा देना, अगले मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Chandan Mitra. ...(*Interruptions*)... You are not speaking. ...(*Interruptions*)... Okay, Mr. Tarun Vijay is speaking. All right.

श्री तरुण विजय : उपसभापति महोदय, धरती को रत्नगर्भा कहा गया है। धरती को जब हम स्पर्श करते हैं तो मां समझकर स्पर्श करते हैं और "पादं स्पर्शं क्षमस्व वे" – धरती से क्षमा मांगते हैं कि ऐ धरती मां, हम पांव से स्पर्श कर रहे हैं। धरती रत्नगर्भा क्यों है क्योंकि उसके हृदय में, गर्भ में जो रत्न हैं, खनिज हैं, पदार्थ हैं, वे सब वसुधा के कुटुम्ब के लिए हैं और उसके हिस्से में आने चाहिए, इसीलिए धरती को वह मातृत्व दिया गया कि जो गरीब लोग हैं, जो सामान्यजन हैं, जो वत्सल भाव से मातृत्व की उपासना करते हैं, उन्हें उसका सर्वश्रेष्ठ उपहार मिल सके। यही बात जीसस क्राइस्ट ने कही थी। Antony saheb, Jesus Christ said, ..(*Interruptions*).. Will you please listen to me? Antony saheb, Jesus Christ said, "Blessed are the meek for they shall inherit the earth." जो गरीब है, जो सबसे अंत में है, जो पिछड़ा हुआ है, वह इस धरती के उपहार को प्राप्त करने वाला सबसे पहला होगा। लेकिन उस धरती मां को यह पता नहीं था कि जो लोग उस गरीब तक धरती के उपहार को पहुंचाने के लिए सदन में भेजे जाते हैं, वे उस सर्वहारा के हाथ से रोटी छीनने के लिए इस बिल को विलम्बित कर रहे हैं। उस धरती का जो हृदय है, उसको जीर्ण-शीर्ण कर रहे हैं। महोदय, मैं पांच साल जनजातीय क्षेत्र में काम करके आया हूं। मैं महाराष्ट्र में जगदलपुर में उन जनजातीय लोगों की दुर्दशा देखकर आया हूं जिनके पास दो जून की रोटी और दो वक्त का कपड़ा

नहीं है। देश के आठ प्रतिशत लोग जनजातीय हैं। उन आठ प्रतिशत लोगों में 98 प्रतिशत आतंकवाद है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि उन गरीब, पिछड़े हुए, अंत में लगे हुए लोगों में 98 परसेंट इन्सर्जेंसी और टेररिज्म है, only in eight per cent Tribal population. खान में अवैध खनन होता था और उस अवैध खनन के कारण उनका विस्थापन होता था। उनकी पीढ़ियां बरबाद हो गयीं, उनको अपने खेतों में मालिकाना हक नहीं मिले। वहां पर मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू लेकर जो करोड़पति और अरबपति आते थे और बड़े-बड़े राजनेताओं को चंदे देते थे, वे उन जनजातियों का खून चूसते थे, उनका शोषण करते थे। मैं वनवासी कल्याण आश्रम में रहा हूं और उस समय हमारे कम्युनिस्ट लोग गोदा ताई पारुलेकर की तलासरी में, लाल बउटा और हमारे जगदलपुर में क्या नारा लगता था, "उस खेत के हर ग़ोशा-ए गंदुम को जला दो, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोटी।" बड़ा अच्छा नारा लगता था। हम गरीबों के साथ हैं, सर्वहारा के साथ हैं, हम सर्वहारा की क्राति करने वाले हैं, हम इस क्षेत्र की जनजातियों में सर्वहारा की सत्ता लाने वाले हैं। आज देश ने देखा कि सदन में सर्वहारा की क्राति करने वाले जमींदारों और सामंतशाहियों के प्रतिनिधि बनकर ये लोग उन गरीबों तक इस खनन का लाभ पहुंचाने में बाधा बन गए, दीवार बन गए। महोदय, विश्व में सारी दुनिया ने देखा, जब लोगों ने मज़ाक उड़ाया। आपको वह वाक्य याद होगा। आपके नेता, स्पोक्सपर्सन का वह वाक्य था, " मिस्टर सीएजी" उन्होंने बड़े ज़ोर से बोला था, "Mr. CAG, where is ₹ 1,70,000 crore thundered the spokesman of the party?" कहां हैं वह 1 लाख 76 हज़ार करोड़ रुपया, बताइए? दूसरे साहब ने कहा, यह सब बेकार की बात करते हैं। क्या घाटा हुआ है? कोई घाटे की बात करते हैं। अरे! Zero sum gain है - ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। कुछ नहीं हुआ है इसमें। लाख करोड़ की बात करते हैं! उस विनोद राय का सारा हिसाब है। वह 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपए का हिसाब गलत है। फिर उन्होंने अपनी वह फेमस लाइन कही, famous for his zero-loss theory, was cock-a-hoop. It is dangerous to look at the situation in 2010 and relate it to 2008. लेकिन हम उत्तर जानते हैं। सर, सारे मुल्क ने देखा है, सच्चाई कैसे सामने आयी। सच्चाई इस तरह सामने आयी कि केवल 199 माइन्स, जो हमने ऑक्शन में रखीं, उनमें से तीस में ही This is The Hindu report, "States to earn ₹ 15,00,000 crores as revenue in thirty years." 15 लाख करोड़ रुपए इन 6 राज्यों को अगले तीस साल में मिलने वाले हैं। इन 6 राज्यों में बीजेपी नहीं होगी, इन 6 राज्यों में आप नहीं होंगे या कोई नहीं होगा, इन 6 राज्यों में हिन्दुस्तान की सरकार होगी...। जो हिन्दुस्तान के गरीबों को यह पैसा देगी। उसमें बाधा बनने वाले कभी माफ नहीं किए जाएंगे। **...(समय की घंटी)...** यह पैसा गरीबों तक जाएगा। **...(समय की घंटी)...**

सर, दुनिया में भारत की कोल माइन्स की क्या स्थिति है? "Five days of auction sees six States reap ₹ 18,000 crores windfall." This was said in a report of The Economic Times. यह पैसा किसको जा रहा है ? यह वहां के मुख्य मंत्रियों की जेब में भी नहीं जाएगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपकी हो या हमारी हो, सिर्फ हिन्दुस्तान फलता-फूलता है। हिन्दुस्तान के गरीबों की गरीबी दूर होती है, तो इससे किसका सपना पूरा होता है? अगर मैं कहूंगा कि दीन दयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा होता है और आपको मेरे साथ कहना चाहिए कि इंदिरा गांधी का भी सपना पूरा होता है। **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, conclude please.

श्री तरुण विजय: श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी को खत्म करने के पक्ष में थीं, गरीबी हटाने के पक्ष में थीं। अगर गरीबी हटानी है, if you think you are the true followers of Indira Gandhi,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tarunji, conclude please.

SHRI TARUN VIJAY: If you think you are the true followers of Mahatma Gandhi, you should have been the very first to support this Bill, without any disturbance.

श्री उपसभापति: तरुण जी, कन्क्लूड करिए।

श्री तरुण विजय: सर, अगर गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी, तो हम कहां जाएंगे? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, उन्होंने नमक को हाथ में लेकर दांडी मार्च शुरू किया था, गरीब के नमक को हाथ में लेकर उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। **...(समय की घंटी)...** अगर आज का हिन्दुस्तान कोयले को लेकर देश की जनजातियों, किसानों, मजदूरों तक लाखों-करोड़ रुपये पहुंचाना चाहता है, तो भारत की संसद सर्वानुमति से, सारे राजनैतिक भेद भूलते हुए, उन गरीबों के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tarunji, please conclude.

श्री तरुण विजय: सर, इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि भारत के सभी राजनीतिक दल भी इसका समर्थन करें। जय हिन्द।

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, खासकर के जो माइन्स एंड मिनरल्स का बिल है और कोल का बिल है...

एक माननीय सदस्य: अभी कोल का बिल नहीं आया है।

श्री शरद यादव: कोल का बिल आया नहीं है, लेकिन आएगा। जहां जंगल है, जहां आदिवासी है, जहां पहाड़ है, वहीं ..। सर, हमें चार मिनट का समय दे दीजिए। हम कम बोलेंगे।

श्री उपसभापति: आपसे कुछ नहीं बोला है। आप बोलिए।

श्री शरद यादव: इस मामले में लोगों की राय अलग-अलग नहीं है। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यह ट्रायबल स्टेट जरूर है, लेकिन जो 68 वर्ष का अनुभव है और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी तो मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके से आते हैं जहां आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका है। हालत यह है कि देश में सबकी बोली है, सबकी आवाज है, सब लोगों का संगठन है- दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का है, अक्लियत का भी है, मजदूरों का भी है, वकील और प्रोफेसरों का भी है, हर एक समाज का संगठन है। एक हिस्सा जरूर है जिसे मूलवासी कहिए, आदिवासी कहिए, वनवासी कहिए, जो जंगल में धकेल दिए गए। मैं इसके इतिहास में नहीं जाता, लेकिन ये लगभग 10-11 करोड़ लोग हैं। आप कह रहे हैं कि यह राज्य को जाएगा, तो अरुण जी, राज्य को जाएगा, अगर इन लोगों को राज्य में बैठा दोगे, तो जो नॉन-ट्राइबल्स हैं, वे सभी धर्म के, किसी एक धर्म के नहीं, उनके साथ न्याय नहीं किया गया है, इतिहास इसकी गवाही देता है। पूरे देश में, हिन्दुस्तान में जहां सबसे ज्यादा लाचारी, बेबसी, गुरबत, लूट है, यह वह इलाका है। वहां पर न इंदिरा आवास है, न वहां पर नहर

बन सकती है, न वहां पानी जा सकता है। हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी भी यहीं है। खेती के बाद अगर हमारे पैर मजबूत करने के लिए कोई ताकत हमारे पास है तो यही है। मैं नरेन्द्र सिंह तोमर जी से segregation के बारे में बात कर रहा था और आपसे भी मेरी विनती है कि आपको अभी समय मिले, नहीं तो जो सलेक्ट कमेटी बनेगी, उसमें भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपनी तरफ से इसको करूं। क्योंकि आदिवासियों के बारे में जितने भी कानून बने हैं, वे कहीं काम नहीं आ रहे हैं। आप पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जो इतना दे रहे हैं, यह पैसा इनके पास कैसे जाए, तो आप इनको कैसे segregate करोगे? यानी इनके हाथ में कैसे जाए? यदि आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना रहे हैं, तो यह बड़ा भारी संकट है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो non-tribal लोग हैं, उन्होंने 68 बरस में ही नहीं अपितु हजारों वर्षों में उनके हक में काम नहीं किया, अब कहां से उनके हक में काम कर लेंगे? इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इस मामले में आप जो यह बिल लाए हैं, मैंने इसको देखा है कि जो non- tribal लोग हैं, इसमें उनको भी तकलीफ है, लेकिन ऐसी तकलीफ किसी दूसरी जगह नहीं है। यदि इन लोगों को राहत देनी है, तो आपको segregate करके कोई न कोई ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी, जैसे हमने तेलंगाना के विकास के लिए एक अलग कमेटी बनाई थी और हमने बुंदेलखंड के लिए भी इसी तरह से कुछ किया है तथा जब भी सूबों में झगड़े होते हैं, तब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। ये जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों से ज्यादा दुखी और तकलीफ में कोई भी नहीं है। आपने इनकी सारी धरती ले ली है। जहां जंगल हैं और जहां पहाड़ हैं, वहां आदिवासी हैं तथा ये आदिवासी वहां हजारों सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं बदल रही है। इस सम्पत्ति में उनका हिस्सा होना चाहिए, आप इनके लिए कहीं से भी कोई रास्ता बनाइए। आप का झारखंड राज्य है, वहां भी खानें हैं, लेकिन आप मुझे इस देश में कोई एक भी ऐसा ट्राइबल बता दें, जो करोड़पति हो। आप अरबपति की की बात तो छोड़ दीजिए। आप मुझे दस करोड़ लोगों में कोई एक आदिवासी बता दीजिए, जो करोड़ रुपए की हैसियत रखता है। ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड): झारखंड में आदिवासी मुख्य मंत्री था, उसको बदल दिया है।

श्री शरद यादव : आप वह बात छोड़ दीजिए। आदिवासी मुख्य मंत्री बनने पर भी झारखंड में लूट कहां बंद हुई? मैं तो यह कह रहा हूं कि आदिवासियों को कहीं भी राहत नहीं है। आप जब तक कानून में राहत नहीं दोगे और उसी के हाथ में राहत नहीं दोगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। यही मेरी विनती है। आप आदिवासियों के मामले में नाम जरूर ले रहे हैं, ट्राइबल स्टेट है, लेकिन उनको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। आप इसका प्रावधान तरीके से करिए।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, सत्ता का अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं आप से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देश का इतिहास पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि जब-जब सत्ता का अहंकार हुआ, तब-तब कहीं न कहीं नाश हुआ, कहीं न कहीं कमी हुई। मैं इतिहास पढ़ रहा था, उसके अनुसार 1993 में जब स्टेंडिंग कमेटी का प्रोविजन हुआ था, उस समय आदरणीय नरसिंहा राव जी देश के प्रधान मंत्री थे, डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी थे। उपसभापति जी, मुझे बताया गया है कि वेंकट रमन साहब भी थे, पाटिल साहब थे और नारायणन साहब थे, उस समय स्टेंडिंग कमेटी का प्रोविजन इसीलिए किया गया था कि चीजों पर आम राय बने। किसी एक पक्ष की हठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति कोई बाल हठ के लिए नहीं है, राजनीति देश के लिए है। हम

[श्री नरेश अग्रवाल]

यहां कोई झुनझुना न पकड़ें कि इसमें हमारा हठ है और हठ करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए स्टेंडिंग कमेटीज़ बनाई गई थीं और उसमें सभी दलों के लोगों को रखा गया था। हम लोग जब राज्य में थे, तब राज्यों में इस बात की मिसाल देते थे कि देश की सरकार ने स्टेंडिंग कमेटीज़ बनाई हैं, इसलिए राज्यों में भी स्टेंडिंग कमेटीज़ बननी चाहिए, ताकि सभी की सर्वसम्मत राय से कुछ बने। हम लोग अपने-अपने राज्य का हित देखने आए हैं। इस बिल से हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोयला हमारे राज्य में नहीं निकलता है। इससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि हमारे राज्य को कुछ मिलने जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि आपको भी हठ नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आज जिस तरह से हठ हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने भी सेलेक्ट कमेटी के लिए साइन किए हैं। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। इन्होंने NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया है। यह कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो पूरे देश में पर्यावरण ठीक हो जाएगा और जो देश में मानक हैं, वे पूरे हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या हालत है? किसान खेत में एक छटांक मिट्टी भी नहीं खोद सकता है, भट्टे पर ईंटें नहीं बन सकती हैं। इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरा नोएडा बरबाद कर दिया है। एक गरीब आदमी अपना घर बनाने के लिए तरस गया है कि वह अपना घर बनाए। आप उसके लिए बिल लाते, अगर आपको गरीबों की चिंता थी, आदिवासियों की चिंता थी। शरद जी कह रहे थे कि कौन सा आदिवासी रईस हो गया? मुझे याद है कि जब नेता जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो हमने विद्यापुर और भदोही में वहां का डेवलपमेंट करके नक्सलवाद को खत्म किया था, नहीं तो आज भी वे लोग जो पानी पीते हैं, शायद उस पानी को हम पी लें, तो हम एक घंटे भी जिंदा नहीं रह सकते, जिस स्थिति में वहां के लोग रह रहे हैं। आपने उनकी क्या बात की? आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खड़ा किया। अगर वे लोग तेंदुआ पत्ता बीनते थे, तो आपने तेंदुआ पत्ते पर रोक लगा दी। आपने इसे भी ठेके पर दे दिया। मैं तो कहता हूँ कि आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भंग कर देना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो हो रहा है, जो-जो आरोप लग रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उसके चेयरमैन पर तमाम आरोप लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे आज फिर कहता हूँ कि न बाल हठ आपको करना चाहिए, न हम बाल हठ में हैं। आज आपको जिद छोड़ देनी चाहिए। चाहे चेयरमैन साहब सब नेताओं को बुलाएँ, चाहे प्रधान मंत्री जी सब नेताओं को बुलाएँ, जब तक सहमति न बने, तब तक आपको इस बिल पर जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह संदेश देना चाहते हैं कि हम राज्यों का भला करना चाहते थे, हम आदिवासियों, गरीबों का भला करना चाहते थे, यह विपक्ष जान-बूझकर रोक रहा है, तो यह मेसेज नहीं जाएगा। आप यह गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि इसकी जिद छोड़िए। आप प्रस्ताव रखिए, आप सब नेताओं को बुलाइए, हम सब बैठे हैं, सबकी बात सुनिए। ऐसा नहीं कि मैं इस बिल के सभी क्लॉजेज़ के विरोध में हूँ, मैं तो इस बिल के 90 परसेंट क्लॉजेज़ के पक्ष में हूँ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : नरेश जी, क्या ये लोग तैयार हैं कि आप सही बात कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग तैयार हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : एक बात बताइए कि सेलेक्ट कमेटी क्या है? सेलेक्ट कमेटी सभी दलों के नेताओं की, सभी दलों के साथियों की बैठक ही तो है। सेलेक्ट कमेटी और क्या है? क्या कोई जिद है कि यह बिल आज ही पास हो जाए? मैंने तो एक सजेशन दिया, आप इसे मानें या न मानें, यह

आपकी जिद है, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप आज इस जिद को छोड़िए, बड़प्पन दिखाइए। हम तो कहते हैं कि नेता सदन, आप खड़े होकर बड़प्पन दिखाइए। **(समय की घंटी)** आप कहिए कि हम सभी दलों के नेताओं को बुलाएँगे और इस पर राय लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इससे 90 परसेंट सहमत हूँ, लेकिन आप जो प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हैं, मैं उस प्रोसीजर का विरोधी हूँ। मेरी राय है कि जिद छोड़ कर हम लोगों को एक साथ मिल कर काम करना चाहिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : कुछ माननीय सदस्यों ने सेलेक्ट कमेटी का जो प्रपोजल दिया है, उसको आपने देखा नहीं है। आपने कहा कि सभी पार्टी के सदस्यों को इसमें समाहित किया गया है। आप ज़रा इसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव दिया है, उन माननीय सदस्यों की मानसिकता क्या है।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जी, मेरे ख्याल में आप और राजीव शुक्ल जी कुछ दिन के लिए बैठ जाते, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बात करेंगे, तो यह ठीक नहीं है। मैं तो खुद खड़े होकर कह रहा हूँ।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : यह गैर-जिम्मेदारी नहीं है, यह आपको मालूम है। आप नाम सुन लीजिए। श्री मणि शंकर अय्यर, श्री शान्ताराम नायक **...(व्यवधान)...**

SHRI P. RAJEEVE: Actually, the Parliamentary Affairs Minister has questioned the mindset of the movers. At the beginning, I said in this House itself, and we all mentioned the importance of the Select Committee and the Standing Committee system. So, I request the Government to consider moving a new Motion. We are ready to withdraw the Motion if the Government is ready. At the beginning, we said that.

श्री नरेश अग्रवाल : मैंने कहा कि आप बड़ा दिल दिखाइए, हमारे दिल छोटे नहीं हैं। जब यूपीए सत्ता में थी, तो हम लोगों ने बहुत कहा, फिर उसे झुकना पड़ा। उधर से नेता सदन का प्रस्ताव आया। आप दिल बड़ा करके रखिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the Government Motion comes, then, that will get precedence. ...(*Interruptions*)... Mr. Rajeeve, in any case, if the Government Motion comes, then, that will get precedence.

SHRI P. RAJEEVE: The Parliamentary Affairs Minister has questioned the mindset. At the beginning, I said it. If the Government is ready to move a Motion, then, we are ready to withdraw our Motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I will just take three-and-a-half minutes. Number one, I appreciate and welcome the laudable objective of the Bill, focused

[Shri Tapan Kumar Sen]

at tribal welfare, as explained by hon. Leader of the House, followed by the hon. Minister of Steel and Mines while presenting the Bill or justifying the Bill. Objectives are quite laudable, but arrangement should be there on the lines of the Bill. There is a serious mismatch. Please go into it. Money going to State does not automatically mean going for tribal welfare and the Bill itself should prepare concrete provisions for that and in that direction the Bill needs to be improved. The second point is, I also appreciate, rather stand encouraged by the concern about the labour working in the mines, as explained again by the hon. Leader of the House. Because of the auction, that arrangement is there. The mines which are operating presently, non-coal mines basically, — for coal a separate arrangement is there — many of the mines which are operating will go to change their hands because of auction process. In consistence with your concern for labour, at least keep a provision in the Bill and also in the Coal Mines Bill that even after the change of hand, change of allottee, the workers working there should not change. Then, all these sympathetic talk about labour will sound realistic. Without ensuring that, don't go on speaking like this because I have personal experience. I worked among the mine workers. I know what is what there. That is why a Select Committee is required to make these improvements, not to scrap the Bill. Thereafter we discussed. Why four hours? We can discuss it in more detail and get it passed. But this improvement needs to be made. Without that, this is just purposeless.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, इस पर विस्तार से चर्चा तो अमेंडमेंट के बाद ही होगी और तभी हम लोग अपना पक्ष भी रखेंगे, लेकिन अभी बिल के स्वरूप के बारे में मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि हम लोग बिल के विरोध में हैं। अगर यह बिल आदिवासियों के उत्थान के लिए और इस तरह के जो दूसरे क्षेत्र हैं, उनके उत्थान के लिए है और इस बिल से उनका फायदा होगा, तो इसमें हम लोग आपके पक्ष में, इस बिल के पक्ष में रहेंगे। लेकिन जो बात कही गई है, वह शायद बिल में नहीं है। बिल में आप लोगों ने यह कहा है कि हम स्टेट को पैसा दे देंगे। लेकिन वह पैसा आदिवासियों को देंगे, उनके उत्थान के लिए देंगे, उनके लिए फिक्स कर देंगे, किसी और को डिस्ट्रिब्यूट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने बिल में मेन्शन नहीं की हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, जिससे उन्हीं लोगों को इससे फायदा पहुंचे।

महोदय, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्हीं की चर्चा के लिए शायद हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट की थी कि अगर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता, तो सेलेक्ट कमेटी में इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार किया जा सकता है और इसके अलावा हमारे साथियों ने भी जो बातें कही हैं, वे सब चीजें भी कमेटी में कंसिडर हो सकती हैं।

अभी लीडर ऑफ दि हाउस ने एक बात कही कि दिक्कत यह है कि ऑर्डिनेंस का पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाद खानें बन्द हो जाएंगी, लोग अनइम्प्लॉइड हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऑर्डिनेंस के लिए भी precedents हैं, एक बार

नहीं, चार-चार बार ऑर्डिनेंस हुए हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजते हैं और अगर एक बार सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए डिसीज़न होता है, तो जो लॉ आज ऑर्डिनेंस के रूप में एग्ज़िस्ट कर रहा है, वही एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास वह पावर नहीं है, आपके पास उसकी पावर है। इसलिए यह एक्सक्यूज़ देकर कि यह ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाना चाहिए और इसके प्रावधानों को डिटेल में नहीं देखा जाना चाहिए, यह सही नहीं है। हमारी यह रिक्वेस्ट है और हम लोगों ने यह बात पहले भी कही थी कि इन प्रोविज़ंस को एवं अन्य सारी चीज़ों को देखकर कि इसमें किस तरह बेस्ट से बेस्ट प्रोविज़ंस आ सकते हैं, तभी इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। अभी देरेक जी ने और हमारे पूर्व सदस्यों ने भी कहा, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी हैं, जो प्वाइंट आउट की जानी हैं और बहुत सी ऐसी खामियां हैं, जिनको दूर करके, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, शायद उनको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

SHRI V. P. SINGH BADNORE (Rajasthan) : Sir, I stand here to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 and also I will talk not on the merits and demerits above, but even on the Statutory Resolution which is here. I don't want to really discuss the merits and demerits or the provisions of the Bill, because that we can discuss only after passing of this Motion either this way or the other way.

But, Sir, let me come to a larger issue. The larger issue here is the eight Ordinances issued. If they are also going to go through the same line, I don't know what will happen. We are really testing the waters here.

Sir, I would like to talk about the model that we have adopted from the West Minister of the British Parliament. Now, in the sixty years of Parliament history in India, we have never come to a situation that has been created today. People have been talking about the tyranny of the other House and some can talk about the tyranny of this House. But, the larger issue here is this. The real point here is, after adopting this model, whether they also had a situation like what we have today. And, let me tell you, they also had a situation like this and it was on the Financial Bills. The same situation had arisen on Financial Bills, in England, about 200 years ago. And, when that situation had arisen, what did they do? I will come to that a little later. That is why what we have adopted is that the Financial Bills do not go to the Rajya Sabha for their passing. That is what we have adopted from the West Minister model of the British Parliament. Sir, the same situation had happened...(*Interruptions*)...Now, here, we have come to a strange situation. So, what happens now? In the British Parliament they have a system and I don't know when and how we can adopt it, because it is going to be a long process. And, if this happens, the whole country can come to standstill and we will not be able to take up any developmental works. What happened in the British Parliament? Let me come to that. Sir, in the Upper House, they stopped

[Shri V. P. Singh Badnore]

a Bill of the House of Commons. It was referred back to the House of Commons with whatever amendments it wanted. And, they do not have a system like we have *i.e.*, Joint Parliament Session. Then, it came back to the House of Lords and it is circumvented. It was then decided that if it is passed twice in the House of Commons, it does not have to be passed in the House of Lords.

SHRI ANAND SHARMA: The House of Commons is not the Council of the States.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: But, we have adopted a system which is very equivalent to that. You can say whatever you want. But, let me say what I want to say. Sir, this is the system that we have got from the British's West Minister model and unless we have something like that, I think, what is going to happen is there is going to be an imbroglio which cannot be sorted out and every Bill cannot go to Select Committee and every Bill cannot be taken all the time to Joint Parliament Session ...(**Time-bell rings**)...Sir, this Bill has already passed through the Standing Committee and the Committee scrutinized the Bill.

This is what I wanted to say, thank you very much.

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपसभापति महोदय, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में किसी भी विधान की जितनी अधिक चर्चा करायेंगे, उतना ही अच्छा विधान उभर कर सामने आयेगा। **...(व्यवधान)...** इसलिए, यदि यह बिल, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जनता से जुड़ा हुआ है, राज्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और चूँकि यह Council of States है, इसलिए इसमें हर बिन्दु पर जब तक सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से विस्तार से चर्चा न हो जाये, तब तक इसे पास नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए हमने सेलेक्ट कमेटी की मांग की है।

माननीय उपसभापति महोदय, बार-बार यह कहा जाता है कि हमारी सरकार इतना रुपया auction से लायी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय उपसभापति महोदय, यह डा. मनमोहन सिंह जी का बयान था कि natural resources should be auctioned. ..(*Interruptions*).. Please listen. It is a fact. Sir, I would like to point out कि 2005 में जब उन्होंने कहा था **...(व्यवधान)...** कृपया सुनिए **...(व्यवधान)...** महोदय, उस समय जब हम लोगों ने auction के लिए मांग की, तो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य मंत्रियों ने auction का विरोध किया था। **...(व्यवधान)...** इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह राज्य की संपत्ति है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश की जितनी भी खनिज संपदा है, वह राज्यों की संपत्ति है, केन्द्र की संपत्ति नहीं है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लीडर ऑफ दि हाउस, जो कि एक विद्वान वकील भी हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप auction का पैसा रोक नहीं सकते। यह केन्द्र सरकार का विवेक नहीं है, यह राज्यों के संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है, इसलिए आपका यह

6.00 P.M.

कथन गलत है। ...**(व्यवधान)**... आपका कथन गलत है कि ordinance नहीं आएगा, तो यह पैसा हम वापस नहीं दे पाएंगे। यह संपत्ति राज्यों की है, आपकी राज्यों को यह पैसा देने की संवैधानिक ड्यूटी है। इसको आप रोक नहीं सकते।

माननीय उपसभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय लीडर ऑफ दि हाउस ने फिर * किया। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने कहा कि यह आदिवासी क्षेत्रों में जाएगा। नहीं, यह सारा पैसा Consolidated Fund of State में जाएगा और राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह इसे आदिवासी क्षेत्र में खर्च करे या नहीं करे।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें केवल हवाबाजी और * करने के लिए, देश को * करने के लिए की जा रही हैं। हम लोग चर्चा से नहीं घबराते हैं, हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन चर्चा कराने से पहले हम हर clause पर, हर बिन्दु पर सेलेक्ट कमेटी में चर्चा कराना चाहते हैं, इसलिए हम सेलेक्ट कमेटी की मांग करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: * is unparliamentary and it is expunged. Now, Shri Sukhendu Sekhar Roy.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order. The Members from that side have said that I misled the House. Please appoint a committee of the House to look into who is misleading the House. ..*(Interruptions)*..

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, as an ordinary student of law and a new entrant to this august House, the Upper House of our great Parliament, I was wondering whether the discussion should be limited to half-an-hour or one hour because, according to me, this is a major Amendment of the original Act. This House ought to have discussed the matter threadbare. Unfortunately, I am disappointed that so much time has not been given for highlighting the provisions of the Bill, one after another. In any case, since I am duty-bound to abide by the ruling of the Chair, I want to make a few points in addition to the suggestions made by my leader in the House, Shri Derek O'Brien. I would urge upon the Government, at the outset, to consider the concerted suggestions given by Shri Derek O'Brien on behalf of our Party. In addition to that, I would like to point out one particular area of our country, that is, Keonjhar district in the State of Odisha.

All of us know that Keonjhar is a very backward district of our country. Everybody will be amused to know that among the top ten tax-payers of this country, three are from Keonjhar. How could it be? Because those three tax-payers from the Keonjhar district do not belong to that area. But, they are the owners of the mines situated in Keonjhar district. So, this is the tragedy of the mining areas of our country. Sir,

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Digvijaya Singh]

according to one of the major provisions of the Principal Act, it is incumbent upon the Government that the Central Government should take all such steps, as may be necessary, for conservation and systematic development of minerals in India. What conservation are we doing, Sir? We cannot add one tonne of any mineral to any mine in this country or anywhere in this world. Whatever the natural resources God has gifted to this country, we are owning that. We cannot add anything to that. We are selling out. We are leasing out. We are extracting. We are finishing. We are ruining without thinking about the conservation of the mines to the extent that it is required for the betterment of the country's economy. Sir, what are we leaving for our next generation? One of the major provisions of this Amendment Bill is that, the ownership will be given or the lease will be granted for 50 years, prospectively and retrospectively, without making any assessment. What about the prospective renewal of fifty years? Is there any assessment made by the Government that the lease is granted before the commencement of this Amendment Bill or the Ordinance? Is there any such assessment made whether those people, who have been granted mining lease are acting according to the provisions of the parent Act? There is no such assessment. Therefore, I would urge upon the Government to make an assessment of each and every lease granted to the lessees and to be granted to the lessees. All these lease contracts should be assessed for the betterment of our economy.

Finally, regarding the issue of Trusts, which my friend from Odisha has highlighted, the State Trust and the National Trust, there is no detail about the formation of the Trusts. My humble suggestion to the Government is that the participation of the State should be more, not only in the State Trust, but also in the process of giving allotment, grant of lease, decision making, e-tendering or whatever the Government is doing. In all the decision-making process, the State Governments must be taken into confidence. Lastly, if at all, this Amendment Bill goes to the Select Committee, that Select Committee must decide the Bill within a definite time-frame and as quickly as possible. The House has the authority under the rules to fix a time that the Select Committee make a report before the Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I rise to support the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015. The NDA Government has taken appropriate steps to promulgate an Ordinance to allocate minerals through auctions. Sir, this Bill...(*Interruptions*)... Sir, let me speak. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति महोदय, क्या यह डिस्कशन शुरू हो गया है? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have said that you will not give names. ...(*Interruptions*)... You all put the names. Why did you speak then? You all gave names and you spoke. Now, you are saying this. ...(*Interruptions*)... Sit down.

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति जी, आधे घंटे का समय आपने दिया था।.....**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only one or two names are there. ...(*Interruptions*)... Shri Jairam Ramesh, Shri D. Raja and Shri Javadekar, only three names are there. ...(*Interruptions*)... Only three more names are there. ...(*Interruptions*)... बैठिए। What do you want?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, take it tomorrow. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना : अब कल कराएं, छः बज गए हैं।.....**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, what? There is the BAC decision to sit up to 7 p.m. You should know that. ...(*Interruptions*)... सात बजे तक बैठने के लिए You should know that. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : अब जो कराना है कल करा लीजिए।....**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is up to you. ...(*Interruptions*)... Okay, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, this Bill is designed to put in place a mechanism for improved transparency in the allocation of the mineral resources, obtaining for the Government its fair share of the value of such resources, attractive private investment and latest technology and eliminating delay in administration so as to enable expeditious and optimum development of the mineral resources of this country, India, which is well endowed in terms of most minerals. However, over the years, the Indian mines and mineral industry is passing through a critical phase by witnessing a negative growth, though mining sector is one of the important sectors in India's economy and contributes around two per cent to its GDP. To address the emerging problems in the mining industry, the Government has promulgated an Ordinance. Although the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 has been amended several times to bring transparency and high efficiency in the field of mining sector, yet several scams were witnessed. In the last few years, the number of new mining leases granted in the country have fallen substantially. Alongside, second and subsequent renewals have also been affected by the court judgements, which led to dependence on import of coal. ...(*Interruptions*)... The present Bill brings in...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, अगर आप चार घंटे का डिस्कशन करा रहे हैं तो हमारी पार्टी को भी 20 मिनट मिलने चाहिए।**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only three more speakers are there. ...(*Interruptions*)... Only three more speakers are there. Sit down. ...(*Interruptions*)... Only three more speakers are there. ...(*Interruptions*)...

हमेशा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It always happens in the House. We always take more time than that is allotted. ...(*Interruptions*)... We have only three more speakers. It always happens.

श्री नरेश अग्रवाल : हमारी पार्टी को कितना टाइम मिला?**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You only gave names. ...(*Interruptions*)... I have not taken any minute. You only gave names, and only spoke. And, now you are saying this. ...(*Interruptions*)... Sit down; sit down.

श्री तरुण विजय : ये सदन में **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...** नरेश जी, **...(व्यवधान)...**

SHRI TARUN VIJAY: How can he disturb the hon. Member? जब मर्जी आती है खड़े हो जाते हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, I want to make it clear. See, now always this House, in any discussion, has taken more time than that is allotted. And, today, I have not taken a single minute. You all gave names, knowing that it is this. Then, what did I do? So, I only allowed you.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it was only half-an-hour. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I asked you to see the board. ...(*Interruptions*)... How many minutes you took? Now, sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: That is not correct. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. ...(*Interruptions*)... You gave all the names and spoke, and now you are preventing others. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Anil Desai to speak.

SHRI P. RAJEEVE: That is not correct. That is showing four hours' discussion. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; it always happens. What is the problem today then? ...(*Interruptions*)... Then, why did you field your name? Why did you field so many names?

SHRI ANIL DESAI: The Bill also proposes to set up a National Mineral Trust created out of contribution from mining leaseholders in order to have a dedicated fund encouraging exploration in the country. So, I would urge upon the hon. Minister to focus his attention on mineral exploration in Maharashtra which is endowed with a lot of minerals. This would provide employment to the youth in our State. Recently, the Government has opened bidding for the initial 21 coalmines. I am happy to note that the offers have already crossed eighty thousand crores. The bulk of it will be going to six key coal bearing States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Jharkhand and my State, Maharashtra. The rest of the money will come as royalty over the lifetime to these mines, so the States need funds. This money will come to States as booster to undertake welfare measures for the people especially the health of the mine labourers who are prone to all kinds of health hazards. This kind of fund should also take care of their basic amenities and overall standards of living. When CAG pointed out that the Government had lost huge revenue on account of allotting coal blocks according to whims and fancies of the UPA Government, my friends in the Opposition had criticised and ridiculed him. When the bids are received of more than eighty thousand crores, I think, the CAG has proved itself. It is a progressive Bill and I support it wholeheartedly. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)...

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): No, Sir. ...(*Interruptions*)... Time is over. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Chandan Mitra, the BAC has decided it on 26th — I checked up that — that the House may sit up to 7.00 p.m. It is already decided. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, we abide by the direction you are giving. But the same BAC has also decided that the debate will be for four hours. Therefore, it cannot be selective for one part. ...(*Interruptions*)... The time was four hours. ...(*Interruptions*)... All of us want to speak. ...(*Interruptions*)... Give them full time. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I would make one thing clear, Sir, that what Ravi Shankar Prasadji has said is that the time allotted was for all the parties. BJP's time

[Shri Anand Sharma]

was 40 minutes. ...(*Interruptions*)... The rest was our time. What is their objection to that? ...(*Interruptions*)... You take your time. ...(*Interruptions*)... You cannot tell me, you cannot dictate to me. ...(*Interruptions*)... It is our decision not to take our time. ...(*Interruptions*)... It is our problem. ...(*Interruptions*)... Don't tell us about our time. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। **...(व्यवधान)...**

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)... Listen to Mr. Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, I wish to make only one point that the UPA Government also.. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, मिनिस्टर को reply के लिए एक घंटा **...(व्यवधान)...** अभी इस पर डिस्कसन के लिए 4 घंटे और चाहिए **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य : जयराम रमेश जी, आपको हम कल सुनना चाहेंगे **...(व्यवधान)...**

SHRI JAIRAM RAMESH: The idea of laying a foundation, in this draft of the Bill, has come from the UPA version of the amendment. ...(*Interruptions*)... But, I want to say that the UPA version of the Bill not only did it...(*Interruptions*)... Almost 200 crores of rupees...(*Interruptions*)... It would be in the fitness of the things to send it to the Select Committee. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA : Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)... In fact, I...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not disturb. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please listen. ...(*Interruptions*)... I have told you that the BAC has decided to sit up to 7.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, when I brought the Statutory Resolution against the Ordinance, my purpose was that the Government should...(*Interruptions*)... I would like to tell the hon. Leader of the House and the Government that the Left parties are second to none in fighting for the development of the nation. ...(*Interruptions*)... The Left parties are second to none in defending the rights of the tribal people and

the poor people. ...(*Interruptions*)... But, this Bill is...(*Interruptions*)... Sir, let me finish. ...(*Interruptions*)... There is a serious amendment. ...(*Interruptions*)... I am not getting into generalities. ...(*Interruptions*)... Sir, there is a serious amendment. ...(*Interruptions*)... In the name of development...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; okay. ...(*Interruptions*)... Shri Javadekar. ...(*Interruptions*)... That's enough. ...(*Interruptions*)... Shri Javadekar. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The Government should allow ...(*Interruptions*)... This will lead to eviction of tribal people and the poor people. ...(*Interruptions*)... This is a very serious thing. ...(*Interruptions*)... That is why the legislation will have to be scrutinized. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, are you speaking? ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: I say that this Bill should be referred to the Select Committee. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: उपसभापति महोदय, **...(व्यवधान)...** मैं इस हाउस का मेम्बर हूँ। **...(व्यवधान)...**

[उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) *पीठासीन हुए*]

प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। **...(व्यवधान)...** मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। **...(व्यवधान)...** मैं तो ऐसे बीच में नहीं बोलता। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at twenty minutes past six of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past six of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now, ...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to say something?

SHRI ARUN JAITLEY: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. Please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am extremely sorry. In the midst of some disturbances, the hon. Member, Mr. Jairam Ramesh, was making a point; and he referred to the 2011 Bill, which he said, the UPA Government had prepared. In fact, I have checked up the facts. In 2006, the Planning Commission had appointed the Anwarul Hoda Committee which went into the whole process of how minerals should be allocated in the country. A 2011 Bill was prepared during the UPA. That Bill – this is only a piece of information and I am partly corroborating what Mr. Jairam Ramesh is saying -- was referred to the Standing Committee. That Bill had a provision for auctions. It also had a provision with regard to first-come-first-serve. Both these provisions were there. Now there was a little bit of confusion as to who would decide when to auction and when to have first-come-first-serve. That Bill went to the Standing Committee. The Standing Committee in the later part of the year 2013 submitted a Report. By that time we were very close to the elections. So, every provision of this present Bill or the Ordinance is what was already a part and substantially had been cleared with the only difference that that alternative option between 'auction' and 'first-come-first-serve' has been eliminated and now you have only 'auction.' That is the only real change. This Bill has already, in its earlier avatar, gone through the Standing Committee once. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: So, the tribal welfare provision which you are claiming is present in the previous one or not.

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, I expect you not to oppose those provisions, and that is the reason that if one is to obstruct merely because it is now we have changed sides, it is a different issue. The fact is that these provisions have been cleared almost entirely. I am saying 'almost entirely' because there is a marginal change. There is no longer a ...

SHRI DEREK O'BRIEN: Closer of mines is missing in this one.

SHRI ARUN JAITLEY: We can deal with that. Now, this Bill has been substantially cleared by the Standing Committee ...(Interruption)... and therefore it is for the hon. House to consider whether any purpose will be served in again sending it to a Committee itself.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. Javadekar.

श्री प्रकाश जावडेकर: मुझे लगा कि नेता सदन के कहने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम भी तैयार हैं और फिर इस लाँग स्टोरी को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि "ना-ना करते चर्चा तो आप कर ही बैठे।" तो चर्चा पूरी क्यों नहीं करते हैं? पूरी चर्चा होती, क्योंकि यह हाउस है डिबेट का, "वादे-वादे जायते तत्वबोधः" और हमारी संसद में यह लिखा है — Discuss, Debate, Decide.

यह रास्ता है डेमोक्रेसी का। आप उसको रोक क्यों रहे हैं? आप जब सत्ता में थे, तब हम कहते थे कि आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? लेकिन आप विपक्ष में आने के बाद भी आप चर्चा से भाग रहे हैं, यह तो अजीब कहानी हो गई! ...**(व्यवधान)**... अब हमारे मित्र, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, जो काग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी चाहते थे कि ऑक्शन करें। तो हमने तो नहीं रोका ना ! हमने नहीं रोका, आपने रोका। ...**(व्यवधान)**... आपने रोका और आपने होने नहीं दिया। मनमोहन जी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपने करने नहीं दिया। आपने उनकी हालत ऐसी की कि एक विद्वान अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री को सीबीआई को जवाब देने को लगाया। यह आपने किया, हमने नहीं किया। यह बिल क्या करता है? यह खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। अब आप किसका विरोध कर रहे हैं? पारदर्शिता का? आपको क्या चाहिए? सर, चिट्ठी से खदानें बंटती थी या रुकती थीं।

एक माननीय सदस्य : चिट से।

श्री प्रकाश जावडेकर : चिट्ठी से..**(व्यवधान)**.. ये लोग "चिरकुट" से बोल रहे हैं। ऐसा है, चिट्ठी आयी है, आती है, आती थी और खदानें बंटती थीं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे विभाग की पूर्व मंत्री थीं, उन्होंने ही बताया। अब क्या करें! पूरा पत्र लिखकर आपको बताया। वे आपकी ही पार्टी की थीं। उन्होंने बताया कि कैसे रुकते थे और कैसे होते थे।

श्री नरेश अग्रवाल : आपने वह सीखा तो नहीं..**(व्यवधान)**..

श्री प्रकाश जावडेकर : नहीं। कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल नहीं सीखेंगे। हम कुछ कर गुज़रने का संकल्प लेकर आए हैं। हम देश का नक्शा बदलेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): नक्शा मत बदलिए..**(व्यवधान)**..

श्री प्रकाश जावडेकर : नक्शा मतलब भ्रष्टाचार का नक्शा बदलेंगे, भ्रष्टाचार की सूरत बदलेंगे। यह है। ..**(व्यवधान)**.. जनता समझ रही है ..**(व्यवधान)**..जनता समझ रही है क्योंकि आपके समय में जो पारदर्शिता आपने नहीं लाने दी, हम उसे तुरंत ला रहे हैं। लोग फर्क समझ रहे हैं। कोल में, मिनरल्स में - टेलीकॉम में 94,000 करोड़ आज तक स्पेक्ट्रम में आए हैं, और भी आएंगे। आप कहते थे कि आए नहीं, सीएजी ने लॉस कर दिया, इसलिए सारे देश में हवा खराब हो गयी और हमें रिज़र्व प्राइस नीचे लानी पड़ेगी क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम का कोई खरीदार नहीं आ रहा है। लेकिन खरीदार आए, और भी आएंगे। अब जैसे कहा कि 32 खदानों में दो लाख करोड़ आए। अगर पूरी 200 खदानें होंगीं तो कितने करोड़ आएंगे? वह राज्यों को मिलेंगे। आप लोग किसका विरोध कर रहे हैं? राज्यों को देने का विरोध कर रहे हैं? यह राज्यों के खजाने में जाएगा, किसी की पॉकेट में नहीं जाएगा। यह मुद्दा निश्चित है, यह फर्क है। यह किसी की जेब में नहीं जाएगा। मुझे बताइए ..**(व्यवधान)**..मैं वही बता रहा हूं। आपका दुख यही है कि यह अब चिट्ठी से नहीं होगा, discretion से नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा कोयले का भंडार, 140 निजी कम्पनियों को 1700 करोड़ टन का कोयले का भंडार आपने मुफ्त में दिया। आपके राज में राशन कार्ड मुफ्त में नहीं मिलता था, वहां इतनी खदानें कैसे मुफ्त में मिलेंगी? वह पैसा कहां गया? पैसा किसने दिया, किसको दिया, क्या हुआ, किसी को तो जानना चाहिए। हम यह सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं। अब इसका क्या विरोध

[श्री प्रकाश जावडेकर]

करेंगे? कोई सजेशन है, अच्छा सजेशन है तो बताइए। मंत्री जी ने पहले ही कहा..**(व्यवधान)**.. लेकिन आपको चाहिए..**(व्यवधान)**.. अगर लोग देखेंगे कि दस साल में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और आपने कहा कि प्रधान मंत्री जी चाहते थे कि ऑक्शन हो लेकिन उन्हें ऑक्शन नहीं करने दिया, यह आपने किया तो लोग फर्क समझेंगे। कौन ऐसा नहीं करने दे रहा था? कहां से चिट्ठी आती थी? यही तो लोग पूछेंगे?..**(व्यवधान)**..

श्री नरेश अग्रवाल : कहां से आती थी?

श्री प्रकाश जावडेकर : चिट्ठी कहां से आती थी..**(व्यवधान)**..

श्री नरेश अग्रवाल : कहां से आती थी, आप नाम बताइए।

श्री प्रकाश जावडेकर : वह तो उनकी मंत्री थीं, हमारे सदन की सदस्या थीं और उन्होंने सब बता दिया। अब क्या करोगे? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि चर्चा से हट रहे हैं। आप हमेशा क्या मांगते हैं कि 4 घंटे नहीं, 6 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए और बोलते भी हैं। तो अच्छा है, यह चर्चा का मंच है, लेकिन अब आप चर्चा से गायब हैं। एक नेता संसद से गायब हैं, आप चर्चा से गायब हैं! यह क्या हो रहा है?.. **(व्यवधान)**.. इससे मिला पैसा राज्यों को जाएगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): एक देश से गायब हैं।

श्री प्रकाश जावडेकर : देश से नहीं, एक नेता संसद से गायब हैं। कहां हैं, आपको भी पता नहीं है। आप ढूंढ़ते रहिए, ढूंढ़ते रहिए। ..**(व्यवधान)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you disturb? ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : इससे मिला पैसा राज्यों को जाएगा, आदिवासियों को जाएगा, उनके कल्याण में लगेगा। इसका आपको दुख है, आप इसका विरोध कर रहे हैं!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please keep quiet. Mr. Javadekar, take only five more minutes.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। I am concluding, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take only five more minutes. I have to put it to vote.

श्री प्रकाश जावडेकर : मैं मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं इस हाउस का मेम्बर भी हूं। सर, मैं इस सदन का सदस्य हूं। आप मेरे राइट्स की रक्षा करिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may take five more minutes. ..(*Interruptions*)... I can stop the Minister also!

श्री प्रकाश जावडेकर: मैंने वही बताया। ...**(व्यवधान)**... आप तरक्की को रोक रहे हैं। आप यह मत समझो कि जनता नहीं समझती। जनता सब समझती है। जनता ने लोक सभा के चुनाव में ...**(व्यवधान)**... दिल्ली को भी आप देखते रहिए। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली में आप कहां हो? आप ढूंढ़ने पर मिल नहीं रहे हो। आपके 24 परसेंट वोट थे, अब 9 परसेंट भी नहीं रहे। आप क्या बात कर रहे हो? ...**(व्यवधान)**...

श्री अविनाश राय खन्ना: अपनी कहानी सुन लो। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर: अगर लोगों ने वहां से हटाया है, तो यहां से भी विदाई निश्चित है, यह आप समझ लीजिए। ...**(व्यवधान)**... आपने क्या-क्या नहीं कहा? आपने जीरो लॉस की बात कही और जीरो लॉस में ऐसे तर्क दिए। आपके पहले वित्त मंत्री थे, वे कह रहे थे मदर अर्थ और वहां पड़ी हुई सारी खदानें और उनमें पड़ा कोयला, वे एक नई philosophy दे रहे थे, ...**(समय की घंटी)**... सर, पूरा कोयला विदेश से, 20 बिलियन डॉलर्स, एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये हर साल कोयले के लिए उन्होंने दिए। ...**(समय की घंटी)**...यह देश पर अन्याय था। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude. ..*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: हम एक पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं? आप जनता को दिए अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, आप आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की व्यवस्था पुनः स्थापित हो, आप इसके लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए देश की जनता इतनी निन्दा करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ..*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं अभी भी कहता हूं कि ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please conclude. ..*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: पी. राजीव विद्ड्रा करने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी conscience को आह्वान करता हूं कि आप इसको विद्ड्रा कर लीजिए और एक बार को कम्युनिस्ट दिखा देंगे कि हम रोकेंगे नहीं, हम रोड़ा नहीं बनेंगे, हम तरक्की के साथ ही रहेंगे, इतना तो करो। ऐसा करने से आपकी इमेज भी बदल जाएगी। आप काम करो। ...**(व्यवधान)**... श्री दिग्विजय जी ने जो कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि अब डा. मनमोहन सिंह जी को बोलना चाहिए क्योंकि डा. मनमोहन सिंह जी के लिए सबके मन में आदर है।...**(समय की घंटी)**... वे भी चाहते थे कि auction होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please conclude. ..*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मेरा आखिरी प्वाइंट है कि जो आपके प्रधान मंत्री थे, वे auction करना चाहते थे। उस समय आपने करने नहीं दिया और अब भी करने नहीं दे रहे हो। ...**(व्यवधान)**... यह तो हद हो गई। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please conclude. ..(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: क्या हुआ ? **...(व्यवधान)...** क्या हुआ ? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ..(*Interruptions*)... Mr. Javadekar, please conclude. ..(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: जयन्ती जी के प्रश्नों का जवाब आपने कभी नहीं दिया। **...(व्यवधान)...** इन्होंने पूर्व मंत्री के प्रश्नों का जवाब ही नहीं दिया। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ravi Shankar Prasad; take only five minutes. ..(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: चिट्ठियां कहां से आती थीं, किस ऑफिस से चिट्ठियां आती थीं। **...(व्यवधान)...**कैसे प्रोजेक्ट्स रोके? ***...(समय की घंटी)...*** देश की तरक्की रोकना सत्ताधारियों का काम नहीं होता, विपक्ष के लोगों का भी नहीं होता। जनता ने हमें इसलिए नहीं भेजा। **...(समय की घंटी)...**आपने उनका सपना अपने समय में भी पूरा नहीं होने दिया और अब भी पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। यह आपका नया पाप है और लोग देख रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, वह गलत है। वह जनता के विरोध में है, देशहित के विरोध में है। **...(व्यवधान)...** इसलिए निश्चित रूप से **...(व्यवधान)...** क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे। **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, I have to dispose it of before 7.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, what can I do? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I have to express my views. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is all. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, देरेक ओब्राईन ने एक मुद्दा उठाया है, जो मेरे विभाग से संबंधित है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please don't do that. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, देरेक ओब्राईन ने closure of mines का मुद्दा उठाया। **...(व्यवधान)...** इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए, हम उस पर ऐसा काम कर रहे हैं **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you take your seat. ...(*Interruptions*)... Now, you please take your seat....(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : इससे न पर्यावरण की हानि होगी, न भावी पीढ़ी को पर्यावरण के ऐसे विनाश का सामना करना पड़ेगा, **...(व्यवधान)..** नई टेक्नोलॉजी आई है।... **...(व्यवधान)...** मैं जानकारी देना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to dispose it of before 7.00 p.m. unless we extend the time. Unless we extend the time...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : उन्होंने सवाल उठाया है, **...(व्यवधान)...** यह मेरे विभाग से संबंधित है। **...(व्यवधान)...** मैं वही बता रहा हूं। **...(व्यवधान)...** आज ऐसा हुआ **...(व्यवधान)...** सर, आज दुनिया में चर्चा का एक ही विषय है। **...(व्यवधान)...** पर्यावरण का विनाश क्या होता है? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please. ...(*Interruptions*)... It is unfair. A Minister cannot do this. ...(*Interruptions*)... A Minister cannot do this. It is unfair. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : खदानों की नई टेक्नोलॉजी है। **...(व्यवधान)..** ऊपर से पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। **...(व्यवधान)...** the closure of mines का ऐसा विषय नहीं आएगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: A Minister should not do this. ...(*Interruptions*)... It is unfair. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : अगर पर्यावरण और चिंता और विकास दोनों साथ-साथ **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: These are dilatory tactics. ...(*Interruptions*)... Dilatory tactics are not good. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, हमारा नारा है, development without ...(*Interruptions*)... हमारा नारा है, पर्यावरण की रक्षा और विकास, दोनों साथ-साथ। **...(व्यवधान)...** अगर यह करना है, तो इसके लिए जो उन्होंने सुझाव दिया **....(व्यवधान)...** हम उसको करना चाहते हैं। **...(व्यवधान)..** आप मेरे भाषण **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ravi Shankar Prasad ji, if he does not... ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. There is a point of order. ...(*Interruptions*)... There is a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI PIYUSH GOYAL (Maharastra): How can he bring in a point of order? ...(*Interruptions*)... He is speaking. He is on his legs. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is not obeying the Chair. ...(*Interruptions*)... If the Minister is not obeying the Chair, what can I do?

SHRI PIYUSH GOYAL: He is responding to the Member's query. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, you had said that he is the last speaker. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to dispose it of before 7.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, Sir, you said that he is the last speaker. There cannot be any other speaker. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This has to be disposed of before 7.00 p.m. So, you sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Let him complete. ...(*Interruptions*)... Let us... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, move the motion for taking it up tomorrow. I have no problem. ...(*Interruptions*)... Then, you move the motion for that. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : जावडेकर जी इस हाउस के मेम्बर हैं। **...(व्यवधान)...** उसके बाद मिनिस्टर का भी reply होगा। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The scope of the discussion is only this amendment. ...(*Interruptions*)... For that, the Minister's reply is... ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मंत्री जी जवाब देंगे और उनका जवाब सुनना पड़ेगा। **....(व्यवधान)..** आप समय बढ़ाइए। **....(व्यवधान)...** हाउस दस-ग्यारह बजे तक चले, कोई दिक्कत नहीं है।**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The scope of the discussion is only this amendment. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : लेकिन मंत्री जी बोलेंगे। अभी हमारे बाकी चार सदस्य बोलने वाले हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : मंत्री जी का reply बाद में। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : कुछ मेम्बर बोलना चाहते हैं। सर, आप हाउस का टाइम बढ़ाइए, टाइम मत रोकिए, बारह बजे या एक बजे तक हो, हमें कोई चिंता नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Today is not the last day of the Parliament, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, हम काम करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, हमें घर जाने की चिंता नहीं है। ...**(व्यवधान)**...एक बार सदन में 12 बजे तक चर्चा हुई थी और हम आगे भी लोकपाल के लिए चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आज 7 बजे जाने की क्या जल्दी है? भाई, आप सबको खाना मिलेगा।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, I am helpless. If the Members are not... ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : यहां भोजन का प्रबंध करेंगे, इसका प्रबंध पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, I have to dispose of this motion. Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Yes, Sir, that is why, I am saying this. ...(*Interruptions*)... सर, मेरा अभी शुरू हुआ है। ...**(व्यवधान)**...एक-एक राज्य का भी बताना है। ...**(व्यवधान)**... क्या आपको पता है ...**(व्यवधान)**... क्या आपको पता है कि ओडिशा को एक लाख करोड़ रुपए मिलेंगे? ...**(व्यवधान)**... ओडिशा को एक लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ...**(व्यवधान)**... डेढ़ लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ...**(व्यवधान)**... इतना पैसा मिलेगा! ...**(व्यवधान)**... आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Ravi Shankar Prasad, take five minutes and then I will put the Motion to vote. ..(*Interruptions*).. Mr. Ravi Shankar Prasad, you have five minutes and then I will put the Motion to vote. ..(*Interruptions*)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : हमारे कई सदस्य बोलने के लिए रह गए हैं। ...**(व्यवधान)**... कई सदस्य अभी बोलने के लिए रह गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to put the Motion to vote. ..(*Interruptions*)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, उनके अधिकारों की रक्षा करना आपके ऊपर है। न केवल हमारी पार्टी के, बल्कि अन्य माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए अगर सदन एक बजे तक चले, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naqvi, do you want to extend the time? If the House agrees, I have no problem. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: No. ...(*Interruptions*)... No. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, जब तक सदस्यों की बात पूरी नहीं हो जाती, तब तक हाउस चले। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House does not agree. ...(*Interruptions*)... There is no consensus. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय मंत्री जी उस पर रिप्लाई देंगे। माननीय मंत्री का रिप्लाई होगा, दो-तीन घंटे रुकना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...** जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...** जो आपने कहा है, उसको सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...** आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...** आप आदिवासियों **(समय की घंटी)** और कमजोर तबकों के साथ क्या कर रहे हैं, उस पर भी सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many minutes do you want? ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Indicate the time. ...(*Interruptions*)... It cannot be unlimited. ...(*Interruptions*)... Sir, there cannot be unlimited time. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... Mr. Naqvi, all right. ...(*Interruptions*)... Now, please. ...(*Interruptions*)... Please, let me say. ...(*Interruptions*)... You are Treasury Benches, let me say. ...(*Interruptions*)... Mr. Javadekar ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, यह मेरा आखिरी मुद्दा है, लास्ट प्वाइंट है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even if you are a Minister, I can take action against you, remember that. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, one last point. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, one last point. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is wrong with you? ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Javadekar, ...(*Interruptions*)... See, these dilatory tactics are not good.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, Sir, we are not doing. ...(*Interruptions*)... You tell them. ...(*Interruptions*)... You tell them. ...(*Interruptions*)...

SHRI PIYUSH GOYAL: We have to respond to the Members. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me say. ...(*Interruptions*)... Listen. ...(*Interruptions*)... Actually, both sides have spoken. I had said only half an hour, but we have taken much more time. Now, I have to dispose of this Motion. Before that, if, I have no objection, Mr. Ravi Shankar Prasad wants to speak and if the Minister also wants to speak, they can speak. But the time should be mentioned. This way I cannot allow. How much time the Minister wants, tell me. Half-an-hour? ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)...

एक माननीय सदस्य : माननीय उपसभापति जी, कम-से-कम तीन घंटे समय और बढ़ा दीजिए, तभी काम होगा। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Half-an-hour, I said. ...(*Interruptions*)... Then we will vote. ...(*Interruptions*)... The Minister wants to speak, okay. ...(*Interruptions*)... The LoP is ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this has to be disposed of today. ...(*Interruptions*)... This has to be disposed of today. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; that is what I am saying. ...(*Interruptions*)... I told this. ...(*Interruptions*)... The hon. LoP himself said that whatever time will be taken by the Minister should be known. So, I have decided ...(*Interruptions*)... I have decided that the Minister will also ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, बिल पर चर्चा नहीं हुई है। **...(व्यवधान)...** ये किस मोशन पर वोट कराएँगे? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please; the House is supreme. If the Minister wants, he will also reply, ...(*Interruptions*)... but not for more than half an hour. After that, I will put the Motion to vote. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, let the speakers finish. After that, we have to dispose of the amendments. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; if the Minister wants, I have to allow. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I think that was the understanding. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the Minister wants, I have to allow. But Mr. Javadekar, nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, last five minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Now, only Mr. Tomar, the Minister, he can take maximum thirty minutes. After that, I will put the Motion to vote. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I also want to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You also want five minutes? Okay, you take five minutes and then the Minister will have thirty minutes. Fine? ...(*Interruptions*)... That's all. It is already very late. ...(*Interruptions*)... Excuse me, it is already very late. ...(*Interruptions*)... You take five minutes; Mr. Tomar will take thirty minutes. After that, the Motion will be put to vote. ...(*Interruptions*)..

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, I have also given my name. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; your party's time is over. ...(*Interruptions*)...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I also ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(*Interruptions*)... No; don't do this. ...(*Interruptions*)... Don't do this. ...(*Interruptions*)... I cannot go by this. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... No, please. ...(*Interruptions*)...

I have given my decision. Five minutes. ...(*Interruptions*)... I have given my decision. Five minutes for Mr. Ravi Shankar Prasad. Maximum thirty minutes for the Minister. Then the Motion will be put to vote. Sit down. ...(*Interruptions*)... No change from that. ...(*Interruptions*)... Okay, Shri Ravi Shankar Prasad.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैं केन्द्र सरकार का मंत्री हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस हाउस का सदस्य भी हूं और सदस्य के रूप में मेरे भी कुछ अधिकार तो बनते हैं। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

माननीय उपसभापति जी, जब हमारे मित्र इस पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाए, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। यह जो कानून है, यह कानून तो उन्हीं का था और स्टैंडिंग कमेटी से एप्रूव्ड था। उसी कानून में ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने कुछ परिवर्तन किया है। लेकिन अभी जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, इस बात को सभी जानते हैं। पीयूष गोयल जी के विभाग में सिर्फ 32 कोल माइन्स नीलाम होती हैं, जिनसे 2 लाख 7,000 करोड़ रुपया आता है और कंज्यूमर्स को 97,000 करोड़ रुपये का बिजली का बैनिफिट मिलता है। इसका क्या मतलब है? आपके समय में भी कोयला सैटलमेंट हुआ था। कहां से चिट चलती थी, क्या चलती थी, नहीं मालूम। सीएजी ने 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का कहा था। अगर 204 माइन्स में से सिर्फ 32 माइन्स को देकर 2 लाख 7,000 करोड़ रुपया सीधे राज्यों को जाता है, तो इसीलिए जाता है क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूं। स्पेक्ट्रम की बात हुई थी, स्पेक्ट्रम को लेकर बहुत आपत्तियां हुई थीं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अब यह विषय कहां से आ गया है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : हमने 60,000 करोड़ रुपये पर शुरू किया था, दूसरे दिन वह 65,000 करोड़ रुपये पर पहुंचा, तीसरे दिन 77,000 करोड़ रुपये पर पहुंचा, चौथे दिन 86,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा, कल 94,000 करोड़ रुपये था और अभी जब मैं यहां से दफ्तर जाऊँगा, तो मालूम होगा कि फिर वह आगे चला जाएगा। इसी सिस्टम में, देश में पूंजी लगाने वाले लोग कहते थे कि अगर यह सब होगा, तो पूंजी नहीं लगेगी। आज वही लोग हम पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। अगर आज हम उसी ईमानदारी को इस कानून में लेकर आ रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्यों है?

महोदय, यहा पर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं बड़ी इज्जत से उनसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं आपने Mines Act में परिवर्तन किया था। जब उस समय के मंत्री वहां पर इसे मूव कर रहे थे, उस समय मैं भी वहां बैठा हुआ था, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पूर्व में, अटल जी की सरकार में मैं भी Minister of Coal and Mines रहा था। माननीय मनमोहन सिंह जी, उस बिल के पास होने के बाद, पाँच-छः साल तक उसे नोटिफाई क्यों नहीं किया गया था? वे कौन सी ताकतें थीं कि आपके द्वारा बिल को पास किए जाने के बाद भी, उसे पाँच-छः साल तक नीलामी के लिए रोका गया? हमें इसका जवाब चाहिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI D. RAJA: We are discussing mines and minerals, not coal.

श्री रवि शंकर प्रसाद : आज मेरे मित्र प्रकाश जावडेकर यह सवाल कर रहे हैं कि जब आप नीलामी के रास्ते पर चले थे, तो नीलामी के रास्ते पर आपको रोकने की कोशिश कौन कर रहा था? **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: Your Chief Ministers. BJP Chief Ministers and later the Supreme Court. Please do not distort the facts. The Minister is deliberately misleading the House ..(*Interruptions*)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : अच्छा, ठीक है, ठीक है।**...(व्यवधान)** आप चीफ मिनिस्टर की कितनी बात मानते हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री अविनाश राय खन्ना : आप सच्चाई तो सुन लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप चीफ मिनिस्टर की कितनी बात मानते हैं, इस पर हम लोग बहस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं इस पर भी बहस करने के लिए तैयार हूं। अब तो मेरे पास और डॉक्युमेंट्स भी हैं, जो पहले नहीं थे, क्योंकि मैं मंत्री हूं। अगर आप फिर बहस करेंगे, तो मेरे पास कई ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं, जो पहले नहीं थे, जो आपकी कारगुजारी को खोलेंगे।

7.00 P.M.

श्रीआनन्द शर्मा: आप यह बात मत करिए। Whom are you threatening? ...*(Interruptions)*... Whom are you threatening? आपके पास कौन से कागज़ हैं, लाइए। धमकी मत दीजिए, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : पहले मुझे अपनी पूरी बात तो बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मुझे बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**... मैं दुनिया समझता हूं और आनन्द जी, अगर कभी आप मौका देंगे, तो हम फिर से बहस करने को तैयार हैं। जब Coal Ordinance पर पीयूष गोयल जी चर्चा शुरू करेंगे, तो काफी बहस होगी, खुलकर बहस होगी कि कौन, कहां पर और कैसे इसको रोक रहा था। आप चिन्ता मत करिए।

मुझे एक बात और कहनी है। आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं और आपकी समय सीमा का भी मैं सम्मान करूंगा। अगर थोड़ा सा बाएं-दाएं हो जाए, तो एलाऊ कर दीजिएगा। हमारे मित्र नरेश जी ने कहा, माननीय सदस्य राजा जी ने कहा, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, बीजेडी की तरफ से दास जी ने कहा और माननीय सुखेन्दु बाबू ने भी कहा, उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, इन्होंने पूछा कि हम ट्राइबल्स का क्या भला कर रहे हैं? माननीय शरद जी ने कहा कि यह ट्राइबल्स के हाथों में जाना चाहिए और राज्यों को अधिकार मिलने चाहिए।

माननीय शरद जी, आप तो देश के बड़े अनुभवी राजनेता हैं। अगर आपने इसकी धारा 9बी को पढ़ा होता, तो आप यह बात नहीं पूछते। पहले इसमें धारा 9ए थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद इस ऑर्डिनेंस में धारा 9बी जोड़ी गई।

इसमें क्या लिखा हुआ है, कि एक District Mineral Foundation एक ट्रस्ट के रूप में बनेगा, जिसमें उनकी चिन्ता की जायेगी, जो माइनिंग से प्रभावित होंगे- व्यक्ति और इलाके। इस Mineral Foundation में कौन-कौन रहेगा, यह राज्य सरकार नियम बनाकर तय करेगी। तो यह अधिकार राज्य सरकार का है। उसके बाद जो व्यक्ति माइनिंग करेगा, तो वह जो रॉयल्टी सरकार को देगा, उसके अलावा एक निश्चित प्रतिशत रॉयल्टी District Mineral Foundation को भी देगा, उस प्रकार से, जो राज्य सरकार नियमों में बनायेगी। तो हम तो इस पूरे कानून में राज्य सरकार का सम्मान कर रहे हैं। एक District Mineral Foundation बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। किसके लिए? आदिवासियों की चिन्ता करने के लिए अथवा इससे जो इलाके प्रभावित होते हैं, उनके लिए। उसमें कौन-कौन होगा, यह राज्य सरकार तय करे। रॉयल्टी का कितना हिस्सा आदिवासियों के लिए जायेगा, यह राज्य सरकार तय करेगी। तो पूरा तो विस्तार से कानून में लिखा हुआ है, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मान्यवर, यह कहां पर लिखा हुआ है, ज़रा दिखा दीजिए। आप तो मंत्री भी हैं। आपने सेक्शन 9बी में यह कहां लिखा है कि आदिवासियों के लिए करेंगे? Affected के लिए कहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक मिनट, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः आप प्लीज़ दिखा दीजिए कि **...(व्यवधान)...** आप दिखा दीजिए कि यह कहां लिखा है? **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद: सतीश जी, **...(व्यवधान)...** आपसे पहले शरद जी बोले, नरेश जी बोले और राजा जी बोले कि minerals rest mostly in the tribal dominated area. Did they say it or not? यह बात सबने कही।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: This is an inference which you are drawing. ....*(Interruptions)*.... ट्राइबल्स की बात नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद: हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं कि inference draw कर रहे हैं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः आपने यह कहा कि हम सबने इश्यू रेज़ किया कि आप ट्राइबल्स को देने की बात कर रहे हैं। इसका कहीं प्रोविजन नहीं है। आप कह रहे हैं कि यह है। **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक मिनट, एक मिनट। **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य: इससे ट्राइबल्स को ही फायदा मिलेगा। **...(व्यवधान)...**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मिश्रा जी, इनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...** इनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...** खुली छूट है। जो बोलना है, बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: बिल्कुल। उस छूट के लिए आपकी इस अनुमति की आवश्यकता नहीं है। **...(व्यवधान)...**

सर, सदन से बड़े सम्मान के साथ मेरा सिर्फ यह कहना है कि अगर यह अधिकार राज्य सरकार को नियम बनाकर है कि उसमें कौन-कौन मेम्बर होगा, उनको नियम बनाकर है कि उस इलाके में जो लोग प्रभावित होंगे, उनको किस तरह से सुविधाएँ दी जायेंगी और उसमें नियम लिखा हुआ है कि रॉयल्टी का कितना परसेंट प्रभावित लोगों के लिए जायेगा, तो राज्य सरकार के पास पूरी छूट है। संसद में हमने इस कानून में क्या लिखा है कि जो माइनिंग से प्रभावित इलाके या व्यक्ति होंगे, तो माइनिंग से प्रभावित इलाके**...(समय की घंटी)...** सतीश जी, आप तो बड़े अनुभवी आदमी हैं, हमने भी देश देखा है। **...(व्यवधान)...**

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, ये यह कहना चाहते हैं कि **...(व्यवधान)...** मान्यवर, इन्होंने यह कहा कि ट्राइबल्स के लिए इसमें प्रोविजन है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए कहीं जिक्र नहीं है। It is only for ....*(Interruptions)*....

श्री उपसभापति: उन्होंने yield नहीं किया। He has not yielded. ....*(Interruptions)*.... He has not yielded. ....*(Interruptions)*....

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, आपने पांच मिनट का समय दिया था। **...(व्यवधान)...** श्रीमन्, आपने पांच मिनट का टाइम दिया था, दस मिनट हो गये। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now finish. ...(*Interruptions*)... He will conclude.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, अब मैं कन्क्लूड करूँगा।

मैंने झारखंड को देखा है, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा, मैंने मध्य प्रदेश में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र को देखा है और मैं विद्यार्थी परिषद के दिनों से आज तक एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने देश को बहुत देखा है और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि खनिज पदार्थ वहीं पर हैं, जहां अधिकांश आदिवासियों की पॉपुलेशन है। यह एक सच्चाई है। क्या आप इसे मान सकते हैं? इसीलिए हमने इस कानून में उसका सम्मान किया है। इसलिए, यह कहना कि उसकी चिन्ता नहीं की गयी है, यह बहुत ही अनुचित है। मैं काग्रेस से फिर कहूँगा कि आप एक बार अपने गिरेबान में ईमानदारी से झांक कर देखिए। आज आप वहां हैं, पहले दस साल आप यहां थे। आपसे कुछ तो खता हुई है! अब कितने साल बाद आयेंगे, देखा जायेगा। आज इस कानून का विरोध करके, सभी वरिष्ठ मित्र मुझे क्षमा करेंगे कि आपने ज़रा भी वैसा संकेत नहीं दिया है कि जनता ने आपका राजनीतिक रूप से तिरस्कार किया इससे आपने कोई सबक सीखा है, ऐसा नहीं लगता है। आज मैं आपसे अपील करूँगा कि अगर ईमानदारी से आप कुछ सोचने को तैयार हैं, तो आपको इस कानून का खुला समर्थन करना चाहिए। यह ईमानदारी का कानून है, पारदर्शिता का कानून है और देश के विकास का कानून है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the Minister will be the next. ...(*Interruptions*)... I have not given the time. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... I have already announced that the Minister will be the next. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, कुछ मेम्बर्स के नाम पहले से दिये हुए हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Your party has taken much more time. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: इनका नाम पहले से दिया हुआ है। **...(व्यवधान)...** डा. चंदन मित्रा का नाम पहले से है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Don't do this. I cannot allow this. ...(*Interruptions*)... I have already announced that the last speaker will be Shri Ravi Shankar Prasad and then the Minister will reply. I have already announced. ...(*Interruptions*)... No more speakers. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, जिनका नाम दिया हुआ है, अगर वे बोलना चाहते हैं, तो उनको बोलने दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, इनका नाम दिया हुआ है, इसलिए इनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't use these tactics. ...(*Interruptions*)... I am fed up with this. ...(*Interruptions*)... I can't suffer this. ...(*Interruptions*)... Both sides are using tactics. ...(*Interruptions*)... Now, Mr. Minister, you reply. ...(*Interruptions*)... After the reply, I will put the motion to vote. ...(*Interruptions*)... I have already announced that. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Your Party has taken more time. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः उपसभापति जी, ट्रेजरी बेंच के लोग ऐसा कर रहे हैं, यह कोई बात है। आप चेयर को इतना defy कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री अविनाश राय खन्नाः इनका नाम दिया गया है। **...(व्यवधान)...**

श्री शरद यादवः आपको बता देते हैं**...(व्यवधान)...** जब तरुण विजय जी बोल रहे थे, उनको समय दिया गया**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Chandan Mitra, I called you. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः मित्रा जी, तरुण विजय जी को आपका समय दे दिया गया। **...(व्यवधान)...** आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Chandan Mitra, I called you and gave you a chance. ...(*Interruptions*)... You said that you don't want to speak. ...(*Interruptions*)... You gave the chance to Mr. Tarun Vijay whose name was not there. ...(*Interruptions*)... Don't do this. ...(*Interruptions*)... You are a very senior and a very honourable man. You are also a journalist. ...(*Interruptions*)... I called your name and gave you a chance. You said that you don't want to speak. You gave the chance to Mr. Tarun Vijay and now you are asking for time. Don't do this. ...(*Interruptions*)... You are such a respectable person, more than a Member. ...(*Interruptions*)... Please don't do this. ...(*Interruptions*)... I am helpless. ...(*Interruptions*)... I can't do that now. ...(*Interruptions*)... I have already announced in the House. ...(*Interruptions*)... Don't you want me to put this motion to vote? ...(*Interruptions*)... I have already announced time of half-an-hour. But, we have taken more than two hours. ...(*Interruptions*)... Everybody spoke. I called your name also. You refused to speak then and now you are asking. Don't do this. ...(*Interruptions*)... I can't allow. ...(*Interruptions*)... I cannot succumb to this kind of pressure. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Now, Mr. Minister. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, before the hon. Minister gives the reply, I had mentioned when the House had reassembled that most of the Members had said that it should be examined by a Committee. Now, all these provisions have already been examined by the Committee. Over and above that, is there anything else that some Members have to say? I still don't know, on merits, what are the views of the Congress

[Shri Arun Jaitley]

Party, which is the prime mover behind this move. Or, is it just that we have to delay even if it was a Bill which originated in our Government and today, we have to create an obstruction in it? Is that the position? Then, it should be made clear to us. It should be clear to my friends here also that they are siding with this move. Otherwise, all these provisions have been substantially cleared by the Standing Committee. If they have any suggestion over and above that, they can let us know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection to that. But, as far as the Chair is concerned, the problem for me is that there is a motion before me. I have to dispose it of. If you agree with the suggestion of the hon. Finance Minister and the Leader of the House, I will be happy. ...(*Interruptions*)... Otherwise, I have to go by the rules and put the motion to vote. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I just wanted to refer to what hon. Leader of the House has said that the Congress is the prime mover behind this. Let it be very clear that we are not the prime mover behind this. Each political party has its own very strong and able leadership, and they are leaders of their own standing. So, I cannot dictate to any political party or its leader, or that my party will decide and they will just sign on the dotted lines. They can take a decision on their own. So, let it be very clear. Everybody has his own views. I cannot dictate to any other political party.

SHRI ARUN JAITLEY: What is your stand on the Bill that you brought in?

SHRI GHULAM NABI AZAD: There have been some amendments and those amendments have not been gone through. That is why, heaven is not going to fall. The hon. Members and the Ministers are saying that they would not be able to pass on this money to the State Governments. Who stops the Government? Once we are done with the first half of the Session, you can go in for second Ordinance and nothing will change. Nothing will change. The law will continue. You can have the second Ordinance immediately after 20th. In the meanwhile, you can have the Select Committee also. There won't be any gap. If hon. Members and all political parties of this side want to go through that in depth, in depth, maybe, whenever we send Members to the Select Committee, or for that matter to the Standing Committee, we send Members who have knowledge, or, much interest. I think they will be able to spend much more time. Here we have 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes, but there is no time-limit there, you can have 10 meetings, you can have 15 meetings, you can have 8 hours long meeting. One can discuss as many times as possible. They can consult Members of the other parties also. They can consult experts also. I want to dispel the impression that we are doing this just for the sake of harassing the Government. That is not our intention, not at all.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you agree with the suggestion made by the Leader of the House?

SHRI GHULAM NABI AZAD: We are all representing different political parties, I can't say on their behalf. Each political party has their own view.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Mr. Minister. Mr. Tomar please. ...(*Interruptions*).. I have to put it to vote.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापति महोदय, आज माइनिंग अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में काफी सदस्यों ने भाग लिया है, लेकिन अगर परिस्थिति सामान्य रहती तो मुझे लगता है कि इससे अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग लेते और अधिक बातें रखते। इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए, उनमें श्री अनिल माधव दवे जी, श्री देरेक ओब्राईन जी, श्री ए. नवनीतकृष्णन जी, श्री कल्पतरू दास जी, श्रीमती गुन्डु सुधारानी जी, डा. अशोक एस. गागुंली जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री तरुण विजय जी, श्री शरद यादव जी, श्री नरेश अग्रवाल जी, श्री तपन कुमार सेन जी, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी, श्री वी.पी. सिंह बदनौर जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री सुखेन्दु शेखर राय जी, श्री अनिल देसाई जी, श्री जयराम रमेश जी, श्री डी. राजा साहब, श्री प्रकाश जावडेकर जी और श्री रवि शंकर प्रसाद जी हैं। इस बिल पर सभी सदस्यों ने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया है, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अगर बिल पर ही चर्चा करने का मानस होता और उतना समय मिलता, तो मुझे लगता है कि माइनिंग मंत्रालय के लिए यह बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता। लेकिन, जिन सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभापति महोदय, सारे देश के ध्यान में है कि यूपीए सरकार के समय पाँच वर्षों तक लगातार खनन का काम प्रभावित रहा, अनेक प्रकार की बातें होती रहीं, देश बदनाम होता रहा। 2जी स्पेक्ट्रम को लेकर, सिंगूर मामले को लेकर, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर अनेक प्रकार के निर्णय हुए और उन निर्णयों से खनिज का क्षेत्र प्रभावित हुआ। अवैध माइनिंग को लेकर शाह कमीशन की स्थापना हुई। शाह कमीशन ने भी अवैध माइनिंग, परिवहन और भंडारण को लेकर कर्णाटक, गोवा, ओडिशा के मामले में अपनी रिपोर्ट दी।

उस पर भी कार्यवाही हुई और उसके कारण देश में एक तरह से खनिज का संकट पैदा हो गया, मजदूरों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया और उद्योग-धंधों को नुकसान पहुंचने लगा। खनिज के क्षेत्र में आप देखेंगे कि 2009-10 में ऑयरन ओर का प्रोडक्शन 218 मिलियन टन था और निर्यात 101 मिलियन टन था। अगर 2013-14 में देखेंगे तो प्रोडक्शन 152 मिलियन टन हो गया और निर्यात 9 मिलियन टन रह गया। अगर हम माइनिंग प्रकरणों के निराकरण की स्थिति को देखेंगे तो 2010 में 68 माइनिंग लीज के आवंटन का प्रॉयर एप्रूवल मंत्रालय के माध्यम से हुआ था, जो 2013-14 में आकर 9 पर रुक गया। एक तरफ माइनिंग के जो केस हैं उनके डिस्पोजल भी प्रभावित हुए, दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ, निर्यात भी प्रभावित हुआ। हम 101 मिलियन टन का निर्यात करते थे, अब हम 5.6 मिलियन टन ऑयरन ओर का आयात कर रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई, और हम लोग मई, 2014 में सरकार में आए, तो मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और उस दौरान

[श्री नरेन्द्र सिंह तोमर]

यह ध्यान में आया कि 63 हजार से अधिक आवेदन राज्यों में और केन्द्र में माइनिंग के ऐसे पड़े हुए हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने विभाग में बातचीत की, मैं स्वयं राज्यों में गया, वहां मुख्य मंत्रियों से बातचीत की, राज्य के खनिज मंत्रियों से बातचीत की, सचिव स्तर पर बातचीत हुई। खनिज क्षेत्र में, इण्डस्ट्री के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम संगठनों से चर्चा हुई और उस चर्चा के आधार पर हम लोग इस दिशा में बढ़े कि जल्दी से जल्दी हमको संशोधन बिल लाना चाहिए और संशोधन बिल लाएंगे तभी यह काम आगे बढ़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, जब हम इस बिल को बना रहे थे तो हम लोगों के सामने दो-तीन उद्देश्य प्रमुख रूप से थे। पहला था आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, दूसरा था खनन को प्रोत्साहित करना, तीसरा था जहां जंगल है वहीं खनिज है और जहां खनिज है और जंगल हैं, वहीं आदिवासी और गरीब आदमी हैं। उनके वेलफेयर और कल्याण के लिए हमारी सरकार को भी कुछ-न-कुछ सोचना चाहिए और तीसरा उद्देश्य था कि जो माइनिंग के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता थी, उससे हम लोग कहीं कम काम कर रहे हैं, इस आवश्यकता को भी हमें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे तीन-चार प्रमुख उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने यह बिल बनाया। हम इसको शीतकालीन सत्र में लाना चाहते थे, लेकिन विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और इस वजह से हम लोग 12 जनवरी को इसे आर्डिनेंस के रूप में लाए। मैंने पूर्व में भी अपनी बात में कहा था कि आर्डिनेंस देश में पहली बार नहीं है, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। माइनिंग का क्षेत्र प्रारम्भ होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में आज जो खनिज के क्षेत्र का योगदान विकास दर में दो प्रतिशत से अधिक का है, यह विकास दर बढ़ाने में योगदान करेगा। खनिज का क्षेत्र रोजगार का सृजन करने वाला है या रोजगार सृजन में योगदान करेगा। इसलिए सरकार ने मजबूरी में और विवशता में देश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अगर कोई मार्ग अपनाया है तो मुझे लगता है कि उसे समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह परिस्थिति नहीं बन पा रही है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से बिल में जो प्रमुख रूप से कुछ प्रावधान हैं, उन पर अपनी बात कहना चाहूंगा और उनका समाधान करना चाहूंगा। सामान्य तौर पर जब यू0पी0ए0 सरकार ने बिल बनाया था तो वह बिल 2011 में लोक सभा में आया। वह बिल लोक सभा में 2011 में आया और लोक सभा की स्टेंडिंग कमेटी को रेफर हुआ। उस स्टेंडिंग कमेटी ने मई, 2013 में इसे विभाग में वापस भेजा और लोक सभा समाप्त होने के कारण वह दोबारा लोक सभा में नहीं आया। महोदय, यूपीए सरकार भी इस बारे में चिंतित थी कि इस में सुधार होना चाहिए और इस से पहले प्लानिंग कमीशन ने होदा कमेटी बनायी थी। वह भी इस बारे में चिंतित थी कि इस कानून में सुधार होना चाहिए। उपसभापति महोदय, हमने तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और बहुत ही साफ नीयत के साथ हम इस कानून को लेकर आए हैं। हां, इतना जरूर है कि जब यूपीए सरकार के समय वह बिल आया था, उस समय आवंटन की प्रक्रिया में auction तो एक रास्ता था, लेकिन auction के अलावा भी अनेक रास्ते थे। अब auction के अलावा बाकी रास्ते भी खुले रहें और पहले आओ, पहले पाओ, यह नीति भी बनी रहे तो मैं समझता हूं कि auction route का उपयोग कौन करेगा? महोदय, जैसी बात, कोल के मामले में कही जाती रही, तो कोल के मामले में तो auction की प्रक्रिया आपने ही शुरू की थी। वह तत्कालीन प्रधान मंत्री जी की ही कल्पना थी, लेकिन नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस पर अमल नहीं हो पाया। अगर अमल हो जाता तो जो 2 लाख करोड़ रुपए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और पीयूष गोयल जी

के कोयला मंत्री रहते हुए मिल रहे हैं, वे सरकार, राज्यों और जनता को यूपीए सरकार के समय में भी मिल सकते थे। लेकिन आप लोगों ने वह अवसर खो दिया। माननीय उपसभापति महोदय, हम ने आवंटन की प्रक्रिया में सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब एक ही रास्ता है और वह auction का है। हम बल्क मिनरल का सीधे माइनिंग लीज के लिए auction करेंगे और जो गैर बल्क मिनरल है, उसका पीएल/एमएल के लिए auction करेंगे। महोदय, अब auction में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और किसी भी प्रकार की bargaining की स्थिति नहीं बनेगी। Auction होगा तो जिस प्रकार से कोल के auction से 2 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जब इस auction की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो चाहे आयरन ओर हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे लाइमस्टोन हो और चाहे अन्य मिनरल्स हों, इनकी नीलामी होगी तब भी इसी प्रकार से राशि आएगी, जो राज्यों के विकास में लगेगी, गरीबों के उत्थान में लगेगी और निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदलने में वह राशि काम आएगी।

माननीय उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि यहां पर जब हम auction की तरफ जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम को exploration को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे यहां इन 66 वर्षों में exploration पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए था। अगर आज चाइना माइनिंग के क्षेत्र में आगे है, कनाडा आगे है, आस्ट्रेलिया आगे है, तो वे इसलिए नहीं कि वे हमारी तरह धीरे-धीरे चल रहे थे बल्कि उन्होंने exploration पर प्राथमिकता से ध्यान दिया। उस कारण निश्चित रूप से उनके यहां खनिज की उपलब्धता हुई और फिर उन्होंने उसे वैल्यू एडेड किया, बेचा और उस वजह से उनकी हालत सुधरी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे भारतवर्ष का पूरा भू-भाग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें माइनिंग की संभाव्यता लगभग 8.13 लाख वर्ग किलोमीटर में सामान्य तौर पर दिखाई देती है और आज इसकी जियोफिजिकल मैपिंग सिर्फ 15 प्रतिशत की ही हुई है। महोदय, माइनिंग लीज पर जो काम हो रहा है, वह टोटल उपलब्ध खनिज के एक प्रतिशत पर ही होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि एक तरफ तो टोटल 8 लाख वर्ग किलोमीटर में 15 प्रतिशत जियो-फिजिकल माइनिंग की मैपिंग हम कर पाए और उसमें भी एक प्रतिशत की ही माइनिंग कर पा रहे हैं। तो जहां देश में हम प्रगति की बात कर रहे हैं, देश को अग्रिम राष्ट्रों की श्रेणी में रखने की बात सोच रहे हैं, महोदय, अगर यह रफ्तार रहेगी, तो हम यह कार्य कैसे कर पाएंगे? इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, हम लोगों ने विचार किया कि exploration की दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। अभी तक केन्द्र सरकार के उपक्रम जो जीएसआई और एमईसीएल हैं, ये एक्सप्लोरेशन के लिए अधिकृत थे। इस बिल में हम लोगों ने यह प्रावधान किया है कि एक्सप्लोरेशन के लिए जो हमारे पीएसयूज़ हैं, उनकी संख्या हम बढ़ाएंगे। यह ऑर्डिनेन्स लाने के बाद हमने एसएआईएल को, एनएमडीसी को, आरआईआईएल को, केआईएसएल को, इनको नोटिफाई किया है और राज्यों में जाकर हमने बात की है कि जो राज्यों के पीएसयूज़ हैं, वे अगर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो केन्द्र सरकार उनको नोटिफाई करना चाहेगी।

माननीय उपसभापति महोदय, इसी के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का प्रावधान किया है। जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन होगा और जो रॉयल्टी की राशि होगी, उसकी दो प्रतिशत राशि इस मिनरल ट्रस्ट में आएगी। यह नेशनल मिनरल ट्रस्ट इस बात की कोशिश करेगा कि हम एक्सप्लोरेशन को कैसे बढ़ावा

[श्री नरेन्द्र सिंह तोमर]

दें और जहां राशि की आवश्यकता होगी, वहां राशि भी प्रदान करेंगे, जहां सहयोग की आवश्यकता होगी, वहां सहयोग की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे, जहां नीति बनाने की आवश्यकता होगी, वहां नीति भी बनाएंगे। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता एक्सप्लोरेशन की है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यह नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया है, जो निश्चित रूप से इस आवश्यकता को पूरा करेगा। तो हम लोगों ने यह प्रावधान किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, चर्चा में कई बार यह बात आती है कि इसमें पट्टे की अवधि 50 वर्ष क्यों कर दी गई है? मैं सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि हम लोगों ने यह अवधि 50 वर्ष की है, लेकिन पहले पट्टे की जो अवधि थी वह 30 वर्ष हुआ करती थी और 20 वर्ष का डीम्ड रिन्युअल हुआ करता था और उस 20 वर्ष के बाद जब सेकेण्ड रिन्युअल की स्थिति आती थी तो अगला रिन्युअल अनन्त काल तक चलता था। इस कारण कुछ लोगों को आजादी के पहले से भी माइन्स मिली हुई हैं और वे माइन्स आज तक चल रही हैं। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने उस अनन्त काल तक की सीमा को घटा कर 50 साल पर लाकर रख दिया है और तय कर दिया कि 50 साल के बाद हर खदान को नीलाम किया जाएगा, उस पर किसी का स्वामित्व या अधिकार नहीं रहेगा। हां, यह सच है कि हम यह जरूर चाहते हैं कि माइनिंग के क्षेत्र में निरंतरता बनी रहे। हम लोगों की कोशिश रही है कि ऑर्डिनेन्स आने के बाद एकदम खनन के क्षेत्र में प्रोडक्शन घट न जाए, प्रोडक्शन बंद न हो जाए और इसलिए हम लोगों ने केप्टिव माइनर की अवधि 15 वर्ष और मर्चेण्ट माइनर की 5 वर्ष की बढ़ाई थी, जिससे कि इस सारे उद्योग में निरंतरता चलती रहे। हमारे मित्र तपन कुमार सेन जी और डी. राजा साहब, पी. राजीव जी, इन माननीय सदस्यों ने भी अपने संशोधनों में आईबीएम की बात कही है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि माइनिंग प्लान के एप्रूवल का प्रावधान जो आईबीएम से एप्रूवल कराने का था, उसको हमने कम नहीं किया है। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि युग परिवर्तन हो रहा है, आजादी के 66 वर्ष हो गए हैं, लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है और लोग अपनी जवाबदारी को महसूस कर रहे हैं। आप सभी के ध्यान में यह आया होगा कि जब प्रधान मंत्री जी ने जन-धन योजना की घोषणा की थी, तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जीरो बेलेन्स पर एकाउंट खोलेंगे, लेकिन जीरो बेलेन्स एकाउंट वाली सुविधा का लाभ सब लोगों ने नहीं उठाया, जिसकी जेब में पैसा नहीं रहा होगा उसने इसका लाभ जरूर उठाया होगा, लेकिन जिस आदमी की जेब में पैसा था, उसने एकाउंट में पैसे जमा कर एकाउंट खोला। इस तरह 12 करोड़ खातों में 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हुई। यह आम नागरिक की जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रकटीकरण है।

माननीय उपसभापति महोदय, इसलिए हम लोगों ने यह जरूर सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो राज्य माइनिंग प्लान को एप्रूव करने की दृष्टि से आईबीएम और केन्द्र सरकार, दोनों के जो मानदंड बनाए हुए हैं, उन मानदंडों के अनुरूप अपनी योजना बना लेते हैं, वह योजना केन्द्र सरकार से एप्रूव करवा लेते हैं, यानी जो केन्द्र सरकार का घटक आईबीएम है उसके मानदंडों के अनुरूप योजना होगी, आईबीएम और केन्द्र सरकार उसे एप्रूव करेगी, तो फिर निश्चित रूप से वे अपने यहां माइनिंग कर सकते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, लेकिन अभी IBM का माइनिंग एप्रूवल हम लोगों ने समाप्त नहीं किया है। यदि कोई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, बढ़ कर काम कर

सकता है, विलम्ब को समाप्त करने का इच्छुक है और अगर IBM के मानदंडों के अनुरूप काम करने की उसकी क्षमता है, तो मुझे लगता है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद कानून में इतनी फ्रीडम किसी राज्य को देने की कोशिश होनी चाहिए, हमने सिर्फ उसी नीयत से उसका प्रावधान किया है, उसके अलावा और कोई दूसरी नीयत नहीं है।

माननीय उपसभापति महोदय, पहले राज्य से मेजर मिनरल्स की फाइल प्रायर एप्रूवल के लिए केन्द्र में आया करती थी। हम लोगों ने इस प्रायर एप्रूवल को समाप्त किया है। हम यह मानते हैं कि हम ऑक्शन पर जा रहे हैं, तो ऑक्शन होने के बाद, फिर केन्द्र सरकार के पास फाइल आए और केन्द्र सरकार में 19 महीने तक उस फाइल की समीक्षा होती रहे, इससे विलम्ब होगा और देश का नुकसान होगा। इसलिए हमने तय किया है कि ऑक्शन हो, राज्य सरकार उसकी सारी वैधानिकता का अध्ययन करे और ऑक्शन में जिससे ज्यादा रकम मिली है, उसे वह माइनिंग लीज़ आवंटित कर दे। राज्यों को यह अधिकार हम लोगों ने देने की कोशिश की है।

माननीय उपसभापति महोदय, यहां DMF की भी बात आई है। बहुत सारे सदस्यों और बहुत सारे दलों ने DMF और बिल के बहुत सारे प्रावधानों का समर्थन किया है। इस बिल में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का प्रावधान किया है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जहां जंगल है, वहीं खनिज है और जहां जंगल और खनिज हैं, वहीं आदिवासी और गरीब हैं। खनन होता है, लेकिन खनन से जो लोग विस्थापित होते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। खनन से जो क्षेत्र प्रभावित होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। राज्य सरकारें गरीबों और पिछड़ों के क्षेत्र में प्लान करती हैं, लेकिन राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं हैं और बंटते-बंटते जो पैसा आता है, वह उस क्षेत्र तक पहुंचते-पहुंचते काफी सिमट जाता है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि खनन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से खनन वाले क्षेत्र में व्यक्ति भी प्रभावित होगा और खनन का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। खनन के क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, खनन का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, वहां व्यक्ति के कल्याण के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन काम करेगा। इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो रॉयल्टी मिलेगी, वह केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित रॉयल्टी की राशि के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, आपने हमसे बोलने के लिए मना किया है और यहां बिल पर बहस हो रही है। इसके बाद सेलैक्ट कमेटी बनेगी और फिर ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given him 30 minutes. बैठिए, बैठिए। I have given him 30 minutes. Let him speak. बोलिए, बोलिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदय, इतनी राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को मिलेगी। हम लोगों ने इसलिए DMF का प्रावधान रखा है और यह जो DMF की राशि जाने वाली है, यह उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च होने वाली है, यह उसी क्षेत्र में खर्च होने वाली है, जहां खनन से व्यक्ति और क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अन्तर्गत एकमुश्त राशि दी जाएगी। वह राशि निश्चित रूप से उस क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हम लोगों ने इस बिल में DMF का प्रावधान करने की कोशिश की है।

[श्री नरेन्द्र सिंह तोमर]

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश में अभी काफी माइनिंग की चर्चा हुई है और कर्नाटक राज्य है, उसके मामले में भी माइनिंग का जो काम रुका, वह सबके सामने जगज़ाहिर है। पिछले दिनों जो बिल था, उसमें यह प्रावधान था कि अवैध माइनिंग में जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसके लिए 2 वर्ष की सज़ा होगी और 25 हजार रुपए ज़ुर्माना होगा। माइनिंग के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि अवैध माइनिंग का धंधा करता है, तो उसके लिए 25 हजार रुपए ज़ुर्माना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी और इसलिए हम लोगों ने 2 साल की सज़ा को बढ़ाकर 5 साल की सज़ा कर दी है और जो ज़ुर्माना था, उसे 5 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से तय किया है। जब 5 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से ज़ुर्माना होगा और अगर किसी के पास 20 हैक्टेयर की माइन है, तो निश्चित रूप से वह ज़ुर्माना बड़ी राशि होगी। इस प्रकार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा सकती है, हम लोगों का ऐसा विचार है। हम लोगों ने राज्य सरकारों के लिए विशेष न्यायालय बनाने का भी प्रावधान किया है। अगर विशेष न्यायालय बनेंगे, तो अवैध माइनिंग के केस जल्दी जाएंगे, उनका जल्दी डिस्पोजल होगा। उनका जल्दी डिस्पोज़ल होगा, अवैध माइनिंग भी रुकेगी और जो लोग पकड़े जाएंगे, उनसे जो राशि आएगी, वह सरकारी खजाने में भी आएगी और निश्चित रूप से हम सब लोग उस दृष्टि से इस काम को करने में सफल होंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, यह सच है कि हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां रखने का विचार किया है, लेकिन जो शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखने की बात है, उसमें राज्यों के प्रति किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की मंशा केंद्र सरकार की नहीं है। जहां एक ओर हम 24 मिनरल्स के स्थान पर 55 मिनरल्स राज्यों को दे रहे हैं, prior approval को समाप्त कर रहे हैं, IBM के approval को भी राज्य चाहें, तो हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं, तो राज्य के किसी मामले में हस्तक्षेप करें, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर एक माइनिंग का प्रकरण साल भर में निराकृत होना चाहिए तो उसकी समय सीमा ज़रूर निर्धारित की जानी चाहिए और अगर समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम सब लोग जल्दी से जल्दी केसेज का डिस्पोज़ल कर सकेंगे। कई बार माइनिंग के क्षेत्र में देखने में आता है कि एक प्रकरण ऐसा है जो 29 साल से चल रहा है, जिले से लेकर दिल्ली तक वह घूम रहा है, लेकिन 29 साल में भी उसका निराकरण नहीं हुआ। इसलिए महोदय, हम लोग यह चाहते हैं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी प्रकरणों का निराकरण करे, उनमें किसी भी प्रकार का विलंब न हो।

माननीय उपसभापति महोदय, यह बात भी मैं आप सबके मध्य निवेदित करना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, पांच मिनट और हैं, पांच मिनट में समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जब बिल ला रही है, खनिज पॉलिसी बना रही है, तो इसका क्रियान्वयन हो, शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हो और देश को इसका फायदा हो, यह भी ज़रूरी है। इसका execution कराना, यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं होना

चाहते हैं। महोदय, हम लोगों ने इसके माध्यम से यह भी कोशिश की है और विलंब को समाप्त करने की भी यह कोशिश है। अभी तक सामान्यतः आर.पी. के लिए जो कंसेशन दिया जाता था, वह 10 हज़ार वर्ग किलोमीटर के लिए दिया जाता था और पी.एल. 25 वर्ग किलोमीटर का दिया जाता था। जब एम.एल. दी जाती थी, तो 10 वर्ग किलोमीटर की दी जाती थी। ऐसा ध्यान में आता है कि कुछ क्षेत्रों में और कुछ खनिजों में जो मानदंड बने हुए हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए महोदय, हम लोगों ने तय किया है कि राज्य सरकार यदि ऐसी आवश्यकता महसूस करेगी और केंद्र को कहेगी, तो एक बार में ही उस खनिज या उस क्षेत्र में इस प्रकार की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बार-बार केंद्र के पास किसी प्रकरण को आने की आवश्यकता न पड़े। पहले आर.पी. कुछ ही लोग करते थे। बड़ी मिन्नत से उन्हें वह मिलती थी, अब आर.पी. के लिए हमने अनेक लोगों को आमंत्रित किया है। कुछ लोग देशहित में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग रिसर्च करना चाहते हैं, वे आएंगे, तो रिसर्च परमिट के लिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने यह ज़रूर तय किया है कि जो आर.पी. करेगा, आर.पी. करने के बाद उसको पी.एल. और एम.एल. का अधिकार नहीं होगा और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, हम लोगों ने ऐसे प्रावधान करने का प्रयास किया है, जिससे कि इस बिल में पारदर्शिता भी बढ़ने वाली है। Mineralization भी बढ़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था में खनिज क्षेत्र का योगदान बढ़ने वाला है, बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होने वाला है, बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलने वाला है और जो माइनिंग का क्षेत्र एक तरह से बदनामी का क्षेत्र हो गया था, वह बदनामी का क्षेत्र खत्म होगा और इस माइनिंग के क्षेत्र की गिनती अच्छे और गति बढ़ाने वाले क्षेत्र में होगी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों और सभी दलों के नेताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बिल हम लोग लेकर आए हैं, यह बिल पारदर्शिता बढ़ाने वाला है, यह बिल रोजगार को सृजित करने वाला है, यह बिल देश की विकास दर को बढ़ाने वाला है, यह बिल जवाबदेही बढ़ाने वाला है और यह बिल देश को आगे ले जाने में सहायक होने वाला है, इसलिए इस बिल को पारित करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, it is time to put the Amendment to vote.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the points raised by hon. Members vindicated our position to move the Amendment, to send the Bill to a Select Committee. There are grey areas and I am pressing for it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are pressing and you are not withdrawing.

SHRI P. RAJEEVE: If the Government is ready, then the Select Committee would be more democratic and the Government can direct the Select Committee to submit a report within a short span of time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you saying that if the Government brings another motion...

SHRI P. RAJEEVE: Otherwise, I will press for the Amendment.

श्री शरद यादव : सर, मेरा एक सुझाव है। यदि सरकार सहमत हो जाती है, सेलेक्ट कमेटी में आप दस दिन, आठ दिन हमें लगा दीजिए, आठ दिन के भीतर हम आपको दे देंगे। **..(व्यवधान)..**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसमें टाइम लगेगा।

श्री नरेश अग्रवाल : दस दिन में कर लेंगे।

श्री शरद यादव : दस दिन कर लीजिए। दस दिन के लिए आप कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए।

श्री एम.वेंकैया नायडु : मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन टाइम आप देख लीजिए। सर, मैंने लास्ट टाइम भी सदन से अपील की थी कि 20 तारीख को सेशन का विराम होने वाला है। उसके बाद हम फिर दुबारा अगले महीने की 20 तारीख को मिलेंगे। यह ऑर्डिनेंस 6 तारीख को लैप्स होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोग बहुत जरूरी मानें तो हम convinced हैं, इसमें और कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। फिर भी अगर बाकी लोगों का ऐसा सजेशन है कि इसको रेफर करें तो रेफर करके उस समय में, यानी सात दिन में इसको वापस लेकर आएं। **..(व्यवधान)..**मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूं। सात दिन में इसे लाएं। **..(व्यवधान)..**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. ..(*Interruptions*)..

श्री एम.वेंकैया नायडु : शरद जी बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारा समर्थन है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Rajeeve, the mover has said that if the Government is bringing another motion for the Select Committee, he is not pressing it. What is your reaction to that?

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Rajeeve's motion by way of an Amendment, my point of order, is infructuous, and I will make good the reasons. It is a settled convention that those who are proposed to be Members of the Select Committee can't speak on the motion for reference to a Select Committee. Most of the Members that he has proposed as Members of the Select Committee, or at least some of them, have participated in the discussion. So, his motion, in any case, which contains the Members of the Select Committee, is infructuous. ..(*Interruptions*)..

SHRI P. RAJEEVE: The discussion is on consideration of the motion.. (*Interruptions*)..

SHRI ARUN JAITLEY: Let me make good the point of order. Before deciding to speak, you should have been aware of Parliamentary procedure. Sir, I refer to Dr. Agnihotri's Praxis of Indian Parliament, published by the Rajya Sabha, page 486.

SHRI P. RAJEEVE: The point of order should be under a Rule.

SHRI ARUN JAITLEY: Please allow me to read and then you will realize when and under what circumstances, during Panditji's period, this convention got established. Sir, Para 32.40 says:

"A Joint/Select Committee is appointed on a motion moved and adopted after introduction of a Bill in the House. At this stage, the Member-in-charge may move that the Bill be referred to a Joint/Select Committee. Any Member, other than Member-in-charge, may also move an amendment for reference of the Bill to a Joint/Select Committee. On adoption of the amendment or the motion, as the case may be, the Bill stands referred to a Select Committee which is composed of Members whose names are mentioned in the motion moved in this regard.

32.41 As per the ruling of the Chair dated 16th September, 1954, Members whose names have been proposed to serve on a Joint/Select Committee should not speak on the motion for reference of the Bill concerning Joint/Select Committee".

...(*Interruptions*)... Let me complete, please.

SHRI P. RAJEEVE: That is not a point of order.

SHRI ARUN JAITLEY: I can be educated if I am wrong.

SHRI P. RAJEEVE: You should.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, it is on Para 32.40, page No. 486. I am citing the convention. And the convention is that somebody of the stature of Dr. Ambedkar was told, either you speak or be on the Committee, you cannot do both. And that is the ruling of the Chair of this House.

Sir, Para 32.41 says:

"As per the ruling of the Chair dated 16th September, 1954, Members whose names have been proposed to serve on a Joint/Select Committee should not speak on the Motion for reference of the Bill concerning Joint/Select Committee. When the motion for concurrence of the recommendation of Lok Sabha to join the Joint Committee of the Houses on the Untouchability (Offences) Bill, 1954 was taken up, Dr. B.R. Ambedkar, whose name was one of the names proposed for serving on the Joint Committee, said that it was impossible for him to remain silent during the discussion on that Bill. He further added that he was aware of the convention that a Member who was on a Select Committee should not speak or take part in the debate on the motion for reference to a Select Committee and that if that convention was to be rigidly followed in the House, he would like his name to be removed from the list of Members to serve on the Committee".

[Shri Arun Jaitley]

The Deputy Chairman said:

"Yes, it is a rigid one; we have been observing it... the convention we have observed in this House is that Members on the Select Committee are not to speak on such a motion. On one or two occasions, permission has been refused... and that is also the convention, I am told, in the other House. I had a talk with the Speaker also about it. A convention if departed from will cease to be a convention. So, it is for Dr. Ambedkar to choose whether he will speak on the floor of the House or be a Member of the Select Committee... It is better that we follow healthy conventions and I see no reason to depart from that convention".

Now, the motion which Shri P. Rajeeve has moved...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: No, I have moved the motion. Not Mr. P. Rajeeve.

SHRI ARUN JAITLEY: The motion which Mr. Jesudasu Seelam, Mr. P. Rajeeve and Mr. Shantaram Naik has moved, comprises of three persons who have participated in this debate and therefore, cannot be Members of the Select Committee. The motion has become infructuous. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir,...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: And the Bill may be put to vote.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Sir, I have some doubt. I would like the Chair to guide me. As a Parliamentary Affairs Minister, I have got some doubt. Thank you, Anand Sharmaji. Leader of the Opposition is also a very senior Member, Anandji is also a very senior Member. I have got a doubt. So far the practice in the House has been that a Member, any Member, normally a Member means the Member who is moving the Bill; but any member can move a motion for referring it to a Select Committee. But in this instant case, other than what the Leader of the House has said, I have another doubt. Shri P. Rajeeve and Shri Jesudasu Seelam have suggested some seven names and I don't think so far that has been the practice for any non-official Member to move a motion, giving these names and asking it to refer to a Select Committee excluding the Government, excluding the supporting parties. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: That is why I said in the beginning. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is not beginning; it is a motion. ...(*Interruptions*)... That is a motion. ...(*Interruptions*)... Mr. Rajeeve, please don't sit and talk. Let us have patience. I have no problem, and I am not going to go away also.

Sir, the motion and the constitution of the Select Committee is done after the consent by the Chair in consultation with the Government. That has been the practice, if I am right. If you say that a Member can have his own choice of people of seven or eight or ten or nine, and then get the motion approved in the House, then, what will happen? Let us try to understand that, and let us be educated on that. I have no problem. Anandji, thank you.

SHRI GHULAM NABI AZAD: First of all, two hon. Members from our side have not spoken; Shri Shantaram Naik and Shri Seelam have not spoken.

SHRI P. RAJEEVE: They are the movers; they are not members.

SHRI GHULAM NABI AZAD: They are the movers; they have not spoken.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Leader of the House has referred to the ruling of 1954. Now, the first question that comes is, do the rules framed and approved by this House take precedence over the ruling referred to, or, does the ruling of 1954 take precedence? ...(*Interruptions*)...Number two, I wish, the Leader of the House is very knowledgeable...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please listen. Let me understand also.

SHRI ANAND SHARMA: And we respect him for that. Sir, under Article 118(1) of the Constitution where both the Houses of Parliament are empowered to make rules for regulating its procedure and the conduct of Business. Now, what is important for me to underscore and to point it out to the learned Leader of the House is that the rules of the Rajya Sabha were first framed on June 2nd, 1964. So, you referred to a ruling of 1954. These rules were brought in to force *w.e.f.* July 1st, 1964. After that, there have been twelve Committees, and all the twelve Committees — this rule book informs us — made amendments to the rules, and this edition — which is the latest edition of the rule book — incorporates all amendments which the twelve Committees had recommended and were incorporated and approved by the House. So, as far as our understanding goes, this motion will be taken up as per this rule book and cannot be otherwise. ...(*Interruptions*)... Mr. Rajeeve, one minute. Number three, what Venkaiaji has said; yes, that does merit consideration. Shri P. Rajeeve, to the best of my recall, himself had mentioned it. Therefore, we were also urging the Government that if the Government were to agree, we could have saved the day and gone home much earlier, that you could have agreed to a Select Committee, which was time-bound. The House has done it in the past. You could have brought the motion. Even now, the House can decide. It is not that what these seven names are. Nobody has any interest. How can there be a Select Committee which excludes the ruling party? There cannot be. Therefore, all of us are here, and let us not make this into a contentious issue. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second; one second. ...(*Interruptions*)... I will allow you. ...(*Interruptions*)... I am calling you.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I recall one incident. The Leader of the House should recall the Lok Pal Bill discussion. ...(*Interruptions*)... Arun Jaitleyji participated in that discussion, and he was the member of the Lok Pal Select Committee. You should remember that. ...(*Interruptions*)... You should remember that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, it is okay. Listen. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I add to the point raised Shri Anand Sharma. It is a valid point. The discussion is not just on one point. This is the discussion on the motion on the Select Committee plus the motion for consideration of the Bill. ...(*Interruptions*)... I have moved it, and this is the property of the House. Nothing can prevent me from pressing it to vote. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, the point raised by Shri Venkaiah Naidu is important. See, because the Select Committee of this House should represent the House.

SHRI P. RAJEEVE: We said it at the beginning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Here, unfortunately, the motion before me is not representing the House. So, what is the solution for that?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, on both counts, Mr. Anand Sharma says that Rules came in the 1960s. Now where Rules occupy that space and say something to the contrary, the past precedent will go. But if Rules do not occupy that area and do not in any way disagree from the past precedent, the present Chair is bound by the past precedent and you have a...(*Interruptions*)... Secondly, Mr. Rajeeve's motion today says I want a seven Member Committee, out of those seven Members, the motion says, in that Committee, he does not mention any Member from the treasury benches or the supporting parties. The motion has to be taken up as it is. He cannot today amend the motion when you are putting it to vote. Now there are two situations which arise. His motion is *prima facie* defective on two grounds. He puts the names of the Members who cannot be Members. It is a parliamentary convention that all Committees have a *pro rata* representation depending on the strength in the House. He does not recognize that factor. So, his motion is an infructuous motion. It cannot be put to vote. You only have the Bill before you. The Bill can either be accepted or rejected. Please put it to vote. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I moved the motion. Actually, I request the Leader of the

House to read the Select Committee provision, 'with the consent of the Members, if they are ready'. I approached several BJP Members. They are not ready to become part of the Select Committee. ...(*Interruptions*)...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: That is an afterthought. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: It is a defective motion. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: I raised a very important point. ...(*Interruptions*)... That is the special contribution of the Leader of the House. ...(*Interruptions*)... In the discussion on the Lokpal Bill, we sent it to the Select Committee and he was a part of that Select Committee. The Rule is very correct. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Today it is a contentious issue. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will give a ruling. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)..

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपसभापति जी, मुझे एक मिनट दें। सर, जिस रूल की बात अभी की गई और हमारे सदन के नेता ने जिसका ज़िक्र किया, मैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहां एक मोशन लाया गया, मोशन लाने से पहले सभी पार्टियों का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन आज यहां जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देखते हुए सत्ताधारी दल के लोगों ने उस सेलेक्ट कमेटी में अपना नाम देने से इनकार किया। **...(व्यवधान)...**

कुछ माननीय सदस्य : किसने कहा? **...(व्यवधान)...**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं यह पूछना चाहता हूँ **...(व्यवधान)...** इसका मतलब यह हुआ **...(व्यवधान)...** इसका मतलब यह हुआ कि अगर सत्ताधारी दल नहीं चाहेगा, तो फिर उस पर सेलेक्ट कमेटी कभी नहीं बनेगी। **...(व्यवधान)... (समय की घंटी)** अगर वे अपने नाम नहीं देते हैं, तो इसमें नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं होता है। सेलेक्ट कमेटी का गठन केवल सत्ताधारी दल की कृपा पर निर्भर नहीं हो सकता। **...(व्यवधान)... (समय की घंटी)**

SHRI GHULAM NABI AZAD: The Chairman is authorized to make the changes and I think the final composition, we can leave it to the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: You give motion to that effect. ...(*Interruptions*)... The only motion which has been moved is not Mr. Ghulam Nabi Azad's motion, it is Mr. Rajeeve's motion and Mr. Rajeeve's motion has sunk. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you not allowing me? ...(*Interruptions*).. Please sit down. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** I have to give a decision now.

8.00 P.M.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If you are going to give your ruling, then I am not going to stand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tell me.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My humble suggestion is that for a solution, there are two ways. One, because the motion moved by Mr. Rajeeve is infructuous because it is not. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is your view. ...(*Interruptions*).. That is his view. ...(*Interruptions*)... Why do you stand? ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: When I speak, nobody should speak, ऐसा कैसे होता है? आप बैठ कर बोलेंगे।

मेरा कहना यह है कि I know my responsibility. ...(*Interruptions*)... अरे भाई, आप सुन तो लीजिए। **...(व्यवधान)...** अगर आपमें इतनी पेशेंस भी नहीं है, तो कैसे चलेगा? **...(व्यवधान)...** That responsibility has been given to me. ...(*Interruptions*)... Please, please. I am talking to the Deputy Chairman. My friends should have some patience and should follow the parliamentary etiquettes also. I have two suggestions. One, this Motion or Amendment to the Bill is infructuous by all standards – by the standards, by the rules and regulations and by the rulings given earlier. Second, coming to the reality of the situation, there are two ways: When we decide about referring it to the Select Committee or not, there are two options: One, Putting the Bill to vote, if they agree; the second alternative is postpone it till tomorrow and let...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you interrupting? ...(*Interruptions*)... What is your problem? ...(*Interruptions*)... What is your problem? ...(*Interruptions*)... Listen to this. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Then, the Chair, the Leader of the Opposition and we, in consultation with each other, can come with a – Sharadji has given a suggestion – revised motion for referring it to the Select Committee, with a time-limit days. ...(*Interruptions*)... Or, in the alternative, let it be taken up tomorrow morning and let all parties meet to...(*Interruptions*)... They do not have confidence in their leaders. Let the leaders meet tomorrow and find out a way if some amendments can be made, as per the wisdom of the Members of the House. That can be taken up tomorrow. Otherwise, let us vote.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. I am not allowing you. ...(*Interruptions*)... How many times should I allow you? ...(*Interruptions*)... No; no. ...(*Interruptions*)... You please sit down. ...(*Interruptions*)... That is enough. ...(*Interruptions*)... This cannot be prolonged like this. ...(*Interruptions*)... Either I will have to take a decision or I will adjourn and go back. ...(*Interruptions*)... I have allowed you two-three times. Please sit down. ...(*Interruptions*)... No; no. ...(*Interruptions*)... No more discussion. ...(*Interruptions*)... You cannot discuss it for three hours. ...(*Interruptions*)... No, I am not allowing you. ...(*Interruptions*)... I am not allowing you. ...(*Interruptions*)... I am not allowing you. ...(*Interruptions*)... I have heard you also. ...(*Interruptions*)... I have heard you twice. ...(*Interruptions*)... Not twice, but thrice. ...(*Interruptions*)... If the House does not want to listen to me, I will adjourn the House. ...(*Interruptions*)...

Two issues have been raised here. The first issue is about the Motion where the hon. Leader of the House has suggested that the Motion is infructuous. That is one point. ...(*Interruptions*)... What do you want? ...(*Interruptions*)... I am helpless. ...(*Interruptions*)... The second point, as mentioned by Shri Venkaiahji, if this Motion is carried with, it does not represent the House. Then, there was some positive suggestion from Sharadji and Venkaiahji. So, I want to comment on both.

As far as the first matter is concerned, I do not question the legality or technicality of the Motion, which has been pointed out by a learned leader like, Arun Jaitleyji. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... I do not question all those things. But the question, before me, is very simple. There is a motion before me. At this stage, I cannot go back and see the technicality or legality of the Motion. And, that Motion can only be withdrawn from the House with the leave of the House, even if that Motion is defective. That means, if it has to be withdrawn, it will have to be put to the House for leave, or I will have to dispose it by voting. Maybe, as for the legality, what he said, may be correct. But as for the Chair, the Chair can now take this decision only because we are at this stage ... ...(*Interruptions*)... No, no. Listen. ...(*Interruptions*)... No, please. We are at this stage and the motion is before the House and the motion has already become the property of the House. Even if it is a defective motion, it is the property of the House and, therefore, I cannot now dispose of it like that. So, the House has to decide it.

Number two, regarding the second suggestion made by Venkaiahji, I want the House to consider that. ...(*Interruptions*)... I want the House to consider that because as the Chairperson, I am to protect the interest of every Member from both the sides. See, I told you, on technicality, the motion can be put to vote and it may be passed or not. ...(*Interruptions*)...

SHRI V.P. SINGH BADNORE: How can you do it? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Why are you interrupting? I am to decide. You come here, sit and do it. ...(*Interruptions*)... No, no. Please. (*Interruptions*)... Let me complete. See, I am not so well versed and learned like Mr. Rajeeve in these matters. So, give me some time. See, I have already ruled the first point that the motion can be withdrawn or rejected by the House only. I cannot take a decision on that. Therefore, if Mr. Rajeeve moves the motion for withdrawal, I will leave it to the House for its consent. Otherwise, I will have to put it to vote. The second is – my real concern – that if this is passed like this, like this ... ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, there is a way out. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying. Let me say that. ...(*Interruptions*)... He has already said that. I know that. He has already said that. Let me say. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is a rule. I will tell you. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After I finish, you can speak. I will allow you to speak. I am not giving a ruling on that. I am only making some observations. You listen to me. The second point is – my concern – that if it is passed, if it is accepted, that doesn't represent this House. It only represents one section of the House. For that, there should be a way out. One suggestion was made by Sharadji, one suggestion was made by Venkaiahji and you have also suggested that this House should find a way out. This House should find a way out. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the way out is here. This is 'Rajya Sabha at Work', page 544. I am referring to para no. 4. Para 3 and 4 should be read together. "But if the amendments of Members are different in content they have been treated separately ..." But what it says, "To the motion for consideration of the Press Council Bill, 1956, three amendments for reference of the Bill to a Select Committee were received, namely, (i) of fifteen members to report within eight days; (ii) of twenty members to report by the first day of the next session; and (iii) of twenty-one members to report by the last day of the first week of the next session. They were moved and put separately as each amendment was considered different ..." Now this can be amended here. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, there is only one motion here. There are no two motions. ...(*Interruptions*)... Give a new motion. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the second last paragraph says, "If the names

given in the original motion for reference of the Bill to a Select or Joint Committee require any change, an amendment is moved for the purpose unless the House agrees to such a change ...."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is only by amendment.

SHRI ANAND SHARMA: So, the amendment can be moved here and now. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no amendment here. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: That is what the rule says. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... See, there is only one motion. There is no amendment here already. So, there is no amendment. ...(*Interruptions*)... No, let me speak. Therefore, if the House agrees, I would suggest, we can decide to send it to a Select Committee, if you want. Then, the Treasury Benches and you sit together and decide the names and decide it. That is the only way.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I agree with what the hon. Member, Shri Anand Sharma, has said. My point is that there is only one Motion before the House, that is, to refer it to the Select Committee, in a particular manner, whether we should vote in favour of it or against it. That will create a very bad precedent and an awkward situation. ...(*Interruptions*)... If they want, Sir, now that you have said, put that to vote ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Put the motion to vote that only Members of the Opposition will be Members of the Select Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not correct. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: If you want such an absurdity, please go ahead. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not fair. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Let the country see that the Opposition wants to have a Select Committee with just Members from the Opposition. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have quoted the past rulings. Why are you getting defensive? ...(*Interruptions*)... It is an after-thought. ...(*Interruptions*)... That is how the amendments have been moved in this House and accepted. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no amendment here now. What do I do? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, amendment can be moved now. ...(*Interruptions*)... Amendment can be moved now. ...(*Interruptions*)... Sir, you may move the amendment. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have given an honourable and a practical solution. ...(*Interruptions*)... Please, please. ...(*Interruptions*)... Nothing is going to happen between now and tomorrow morning. Let Leaders meet. Let us discuss among ourselves about ways and means of referring it to the Select Committee, as said by Sharad Yadavji, about the composition and about the time also. ...(*Interruptions*)... Or, otherwise, put the motion to vote. ...(*Interruptions*)... Put the motion to vote. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Venkaiahji's suggestion is ...(*Interruptions*)... Venkaiahji's suggestion is, tomorrow morning, Leaders would sit and decide the names for the Select Committee. Why don't you agree for that?

SHRI P. RAJEEVE: No, Sir....(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I propose that amendments should be brought right now and, in consultation with the Leader of the House and Parliamentary Affairs Minister, the names can be drawn from that side and this side also. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, here the Rule says, you cannot take anybody's name without his consent. Consent cannot be obtained like this. ...(*Interruptions*)... If you want to be there ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Everybody is here. ...(*Interruptions*)...

श्री एम. वेंकैया नायडु: गुलाम नबी आज़ाद जी, आप इतने अनुभवी हैं। ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we can adjourn for ten minutes and we can do this. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, as Parliamentary Affairs Minister, I have given a practical suggestion, that is, let us have some time, discuss among ourselves. And the manner and the time ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we need to take the consent. What is the problem? ...(*Interruptions*)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, what Mr. Venkaiahji has

suggested is right. Let us sit in the morning and deliberate on the names for the Select Committee. That is okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, that is okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, let the names be decided in the morning. He is right. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me ask you one thing. ...(*Interruptions*)... Now, what I am saying is, Venkaiahji's suggestion is that Leaders can sit and finalize the names for the Select Committee and also the time frame. ...(*Interruptions*)... Why don't you accept that? ...(*Interruptions*)... Because, for me ...(*Interruptions*)... I feel guilty to sit in the Chair and pass a one-sided resolution like this. That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... Therefore, I am making the announcement. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: That is what we had been saying since the beginning. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yeah, yeah. That is okay. ...(*Interruptions*)... It is after discussion. Therefore, on the basis of the consensus in the House, I am not putting the motion now to vote. The consensus is that tomorrow morning, Leaders will sit ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why? ...(*Interruptions*)... Now, please. ...(*Interruptions*)... Are you not agreeing? ...(*Interruptions*)... Let me complete. In the morning, the Leaders, the LoP, the Leader of the House, the Parliamentary Affairs Minister and Leaders of Parties would sit together and prepare the names for the Select Committee, and that will be put here and unanimously passed. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, we have no problem with that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: And tomorrow, the time also will be decided, within how many days it will be done. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Right, Sir. We agree. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you oppose it? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this means the House decides that this Bill will be referred to a Select Committee. The Leaders will sit together tomorrow and the composition and time will be decided. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have announced...(*Interruptions*)... I am announcing it as a consensus decision of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय उपसभापति जी, इसका मतलब यह हुआ कि सेलेक्ट कमिटी बनाई जाएगी, यह तय हो गया। कल केवल उसकी कॉम्पोज़ीशन तय होगी। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: हो गया।...**(व्यवधान)...**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: ठीक है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I have announced the decision. Tomorrow morning, the LoP, the Leader of the House, the Parliamentary Affairs Minister, party leaders and I will also sit, along with hon. Chairman, to decide the names and the time frame by which it has to complete it.

Now, the House stands adjourned till 11.00 A.M. on Wednesday, the 11th March, 2015.

The House then adjourned at sixteen minutes past

eight of the clock till eleven of the clock on

Wednesday, the 11th March, 2015.